



पंजाब की जनता को एनएफएसए के तहत मिलने वाले गेहूं से अलग ये किट दी जाएगी: भगवंत सिंह मान

इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब के लाखों गरीब और दलित परिवार को होगा: हरपाल सिंह चीमा

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

पंजाब में पहली बार व्यापक स्तर पर खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूती देने के उद्देश्य से ऐतिहासिक पहल करते हुए मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान ने आज मेरी रसोई योजना की शुरूआत का ऐलान किया, जिसके तहत 40 लाख परिवारों को अप्रैल से तिमाही आधार पर मुफ्त फूड किट (भोजन किट) का वितरण शुरू किया जाएगा उल्लेखनीय है कि ये फूड किट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिए जाने वाले गेहूं से अलग तौर पर प्रदान की जाएगी।

इस योजना की शुरूआत करते हुए मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार जन कल्याण योजनाओं के लिए संसाधन जुटाना अच्छी तरह जानती है, जो पूरी

ईमानदारी और दूरदर्शिता के साथ चलती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर बच्चे के लिए पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करना सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि हमारा नैतिक फर्ज है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले लोक-हितैषी बजट में भी समाज के हर वर्ग के हितों का ख्याल रखते हुए लोक भलाई उपायों का दायरा और विस्तृत किया जाएगा।

मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह पहल पंजाब के हर परिवार के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। देश को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में पंजाब के शानदार योगदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के मेहनती और जुझारू किसानों ने अथक मेहनत से यह



सुनिश्चित किया कि देश में कोई भी भूख न सोए। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य ने देश का पेट भरने में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हालांकि पंजाब में अभी भी कुछ परिवार ऐसे

हैं, जो अपनी रोजी-रोटी के लिए रोज संघर्ष करते हैं, जिनकी मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह महत्वाकांक्षी 'मेरी रसोई योजना' शुरू की है।

इस योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य सरकार 40 लाख परिवारों को फूड किट प्रदान करेगी। प्रत्येक किट में मासिक खपत के लिए दो किलो दाल, दो किलो चीनी, एक किलो नमक, 200 ग्राम हल्दी पाउडर और एक लीटर सरसों का तेल होगा। ये फूड किट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत योग्य लाभार्थियों को पहले वितरित की जा रही गेहूं से अलग तौर पर प्रदान की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि मार्केट डेवेलपमेंट एजेंसी के रूप में काम करेगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि मार्केट डेवेलपमेंट एजेंसी के रूप में काम करेगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह पहल यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य के हर बच्चे को पौष्टिक भोजन मिले, जो पंजाब भर में खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूती देगा। उन्होंने ऐलान किया कि इन किटों का

वितरण अप्रैल में शुरू होगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अप्रैल महीने से शुरू होकर हर तिमाही के बाद इन किटों का मुफ्त वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिया कि किटों की हाटल में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पंजाब सरकार सप्लाई की जाने वाली सभी खाद्य वस्तुओं की सख्त गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि खराब गुणवत्ता या अनियमित सप्लाई संबंधी किसी भी शिकायत से सख्त से निपटा जाएगा। अपनी सरकार की लोक-हितैषी सोच का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हमारी सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए हृदय प्रतिक्रिया देती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का आगामी लोक-हितैषी बजट पंजाब के लोगों के लिए भलाई उपायों को और मजबूत करेगा।

वितरण अप्रैल में शुरू होगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अप्रैल महीने से शुरू होकर हर तिमाही के बाद इन किटों का मुफ्त वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिया कि किटों की हाटल में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पंजाब सरकार सप्लाई की जाने वाली सभी खाद्य वस्तुओं की सख्त गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि खराब गुणवत्ता या अनियमित सप्लाई संबंधी किसी भी शिकायत से सख्त से निपटा जाएगा। अपनी सरकार की लोक-हितैषी सोच का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हमारी सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए हृदय प्रतिक्रिया देती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का आगामी लोक-हितैषी बजट पंजाब के लोगों के लिए भलाई उपायों को और मजबूत करेगा।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल लक्ष्य व्यक्ति

निर्माण, राजनीति नहीं: डॉ. मोहन भागवत

एजेंसी (हि.स.)

देहरादून

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि संघ किसी राजनीतिक दल का अंग नहीं है और न ही चुनावी राजनीति उसका उद्देश्य है। संघ व्यक्ति निर्माण का कार्य करता है, क्योंकि व्यवस्था तभी सुदृढ़ रहती है, जब व्यक्ति सुदृढ़ हो।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. भागवत दो दिन के प्रवास पर उत्तराखंड में हैं। आज प्रवास के दूसरे दिन डॉ. भागवत हिमालयन कल्चरल सेंटर के प्रेक्षागृह में पूर्व सैनिकों और पूर्व सेना अधिकारियों के साथ विशेष संवाद गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। डॉ. भागवत ने कहा कि संघ बिना साधनों के खड़ा हुआ और दो बार प्रतिबंध के बाद भी समाज के बल पर आगे बढ़ा। संघ का स्वयंसेवक आत्मिक शक्ति से प्रेरित होकर समाज परिवर्तन के लिए कार्य करता है। डॉ. भागवत ने स्पष्ट किया कि संघ का उद्देश्य प्रचार नहीं, बल्कि समाज का संघटन और राष्ट्र का उद्धार है। संघ नहीं, समाज के कारण देश बड़ा हुआ, यही इतिहास में दर्ज होना चाहिए। उन्होंने संघ की प्रारंभिक जानकारी देने के साथ ही स्थापना वर्ष 1925 से लेकर 2025 तक की यात्रा के



प्रमुख बिंदुओं को पूर्व सैनिकों के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि देश के भाग्य निर्माण में समाज की भूमिका सबसे बड़ी होती है। समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र की रक्षा भी संभव होगी। समाज का बल ही सबको बलवान बनाता है, इसलिए समाज को नेतृत्व चरित्रवान और संगठित होना आवश्यक है। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध का उदाहरण देते हुए बताया कि इंग्लैंड युद्ध के लिए तैयार नहीं था और जर्मनी पूरी ताकत के साथ युद्ध के मैदान में

था, तब चर्चिल का मंत्रिमंडल ने भी समझौते की बात कही, लेकिन चर्चिल ने नागरिकों से बातचीत के बाद युद्ध का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि जनता ने चुना है और यदि जनता युद्ध चाहती है तो चर्चिल ने युद्ध का निर्णय लिया। डॉ. भागवत ने वर्ष 1857 की क्रांति की विफलता का भी जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि उस समय भारत में वीरता, शौर्य और सहसास की कमी नहीं थी, फिर भी हार हुई। वीरों ने संघर्ष किया,

भले ही वे पराजित हुए, लेकिन स्वतंत्रता की ज्योति बुझी नहीं। इसके बाद भी क्रांतिकारी आंदोलनों ने देश की आजादी के लिए निरंतर संघर्ष जारी रखा। आरएसएस के सर संघचालक ने कहा कि स्वतंत्रता तक सभी ने एकजुट होकर संघर्ष किया लेकिन स्वतंत्रता के बाद देश की राजनीति स्वार्थी की ओर मुड़ गई और कई राजनीतिक दलों का जन्म हुआ। अग्रजों के खिलाफ लड़ाई समाज सुधार के बिना संभव नहीं थी इसलिए जातिगत

भेदभाव से ऊपर उठकर समाज को एकजुट करना आवश्यक था। उन्होंने कहा कि आज कई राजनीतिक धाराएं हैं और इससे विकृति भी उत्पन्न हुई है।

उन्होंने संघ के प्रथम सर संघचालक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार के चिंतन व राष्ट्रभक्ति को लेकर कहा कि वे जन्मजात राष्ट्रभक्त थे और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय व निर्भीक भूमिका निभाई। गुलामी के प्रति उनमें तीव्र रोष था। वर्दमारम समेत अन्य आंदोलनों में सक्रिय रहे और जेल भी जाना पड़ा, लेकिन वे मातृभूमि के संघर्ष करते रहे। उन्होंने कहा कि आज आरएसएस व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण में जुटा हुआ है।

डॉ. भागवत ने कहा कि भाषा, पंथ, देवी-देवता और परंपराएँ भिन्न हो सकती हैं, लेकिन हमें जोड़ने वाला एक सूत्र है, उसे मजबूत करना होगा। उन्होंने सेकुलर शासन व्यवस्था को यूरोपीय अवधारणा बताते हुए कहा कि भारत का स्वभाव विविधता में एकता का है। सत्य को एक ही रूप में नहीं देखा जा सकता। हमारे ऋषियों और पूर्वजों ने विश्व कल्याण की भावना से इस राष्ट्र की आकांक्षित रखा। डॉ. भागवत ने कहा कि हिंदू शब्द इस देश की पहचान है। यह मानवता और विश्व कल्याण का भाव लिए हुए है।

भारत टैक्सी से जुड़े चालकों के लिए न्यूनतम आधार किराया तय होगा : अमित शाह

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि हाल ही में शुरू की गई सहकारी टैक्सी सेवा भारत टैक्सी अपने मंच से जुड़े सभी हब्स/सर्विसेंटर (चालकों) के लिए प्रति किलोमीटर न्यूनतम आधार किराया सुनिश्चित करेगी और इस दर से नीचे सेवा संचालित नहीं की जाएगी।

शाह ने यहां भारत टैक्सी के सारथियों के साथ संवाद करते हुए कहा कि मौजूदा टैक्सी एग्रीगेटर कंपनियों ने अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए चालकों के लिए कोई आधार दर तय नहीं की है, जबकि भारत टैक्सी में ऑटो की लागत, पेट्रोल की खपत और न्यूनतम लाभ को जोड़कर बेस रेट निर्धारित किया जाएगा। यह सेवा पारदर्शिता के सिद्धांत पर काम करेगी और किसी भी बदलाव की सूचना एक सप्ताह पहले सारथियों को मोबाइल पर दी जाएगी।

अमित शाह ने कहा, भारत टैक्सी में कुछ भी छिपा नहीं होगा। सारथियों को नोटिफिकेशन के जरिए हर जानकारी देने से हबभारत टैक्सी हब दुनिया की सबसे पारदर्शी कैब सर्विस बनेगी। भारत टैक्सी सारथियों की मिनिमम वार्यबिलिटी के आधार पर एक बेसलाइन किलोमीटर रेट तय करके चलेगी। भारत टैक्सी में ऑटो के मूल्य, पेट्रोल की खपत और मिनिमम प्राइफ टको मिलाकर एक बेस रेट बनाया जाएगा और सर्विस इस रेट से नीचे नहीं



चलेगी।

उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य किसी निजी कंपनी की तरह अधिकतम मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि सारथियों को सशक्त बनाना है। इस सहकारी मॉडल में सारथी ही मालिक होंगे और 500 रुपये का शेयर लेकर साझेदार बन सकेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चुनाव में सारथियों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी, ताकि वे स्वयं अपने हितों की रक्षा कर सकें।

शाह ने कहा कि भारत टैक्सी की आय का 20 प्रतिशत पूंजी के रूप में संस्था के खाते में रखा जाएगा, जबकि 80 प्रतिशत राशि सारथियों को उनके द्वारा चलाए गए किलोमीटर के आधार पर लौटाई जाएगी। शुरूआती तीन वर्षों में विस्तार पर ध्यान दिया जाएगा, इसके बाद लाभ का वितरण इसी अनुपात में होगा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि आने वाले तीन सालों में देश के प्रत्येक नगर निगम में हबभारत टैक्सी हब मौजूद होगी।

उन्होंने कहा कि सहकारिता के सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है और उदाहरण देते हुए अमूल का उल्लेख

किया, जहां लाखों महिलाओं ने छोटे निवेश से बड़ी सहकारी संस्था खड़ी की है। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी भी इसी प्रकार का एक बड़ा सहकारी आंदोलन बनेगी और आने वाले तीन वर्षों में देश के प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी।

महिला सशक्तीकरण के तहत हबभारत टैक्सी की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए अमित शाह ने कहा कि ऐप में ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि एकल महिला यात्री को प्राथमिकता से महिला सारथी उपलब्ध कराई जाए, जिससे सुरक्षा और आत्मनिर्भरता दोनों सुनिश्चित हों।

उन्होंने कहा कि सारथियों की शिकायतों के निवारण के लिए वेबसाइट पर विशेष विंडो बनाई जाएगी और फीडबैक के आधार पर नीतियों में लगातार सुधार किया जाएगा। उन्होंने सारथियों से आग्रह किया कि वे स्वयं को ड्राइवर नहीं, बल्कि गौरव के साथ हबभारत टैक्सी हब और सहकारिता के इस मॉडल को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

रांची से दिल्ली जा रहा एयर एंबुलेंस चतरा के जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त

एजेंसी (हि.स.)

चतरा/रांची

झारखंड के चतरा जिले से एक विमान हादसे की खबर सामने आई है। रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुआ एक एयर एंबुलेंस विमान सिमरिया थाना क्षेत्र के घने जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विमान में सवार सात लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है।

बताया जा रहा है कि आपात स्थिति में एक रांपीर मरीज को दिल्ली ले जाया जा रहा था। विमान में मरीज के साथ एक परिजन, एक डॉक्टर, एक मेल नर्स और चालक दल के सदस्य सवार थे।



इनमें पायलट विवेक विकास भगत, स्वराजदीप सिंह, मरीज संजय कुमार, अर्चनादेवी, ध्रुव, डॉ. विकास कुमार गुप्ता, सचिन कुमार मिश्रा शामिल हैं। उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद विमान का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल

(एटीसी) से टूट गया और वह रडार से गायब हो गया। इसके बाद सिमरिया क्षेत्र के खासियातू करम टांडू के जंगलों से तेज धमाके की आवाज सुनाई देने की सूचना स्थानीय ग्रामीणों ने दी।

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विमान को आसमान में अस्तित्वलित हालत में उड़ते देखा गया, जिसके कुछ ही देर बाद वह जंगल में जा गिरा। दुर्घटना स्थल दुर्गम और घने जंगलों से घिरा होने के कारण राहत और बचाव कार्य में कठिनाई आ रही है। सूचना मिलते ही सिमरिया थाना पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है और मलबे तक पहुंचने

की कोशिश की जा रही है।

प्रशासन का प्राथमिक फोकस शवों को बाहर निकालने और घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच प्रक्रिया शुरू करने पर है। अभी तक विमान में सवार लोगों की आधिकारिक पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। हादसे के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। लेकिन तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। मामले की जांच के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को सूचित किए जाने की जानकारी मिली है। प्रशासन ने विस्तृत रिपोर्ट आने तक किसी भी तरह की अटकलों से बचने की अपील की है। पुलिस के एक वरीय अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है।

मेडिकल ट्रेवल इकोसिस्टम होगा मजबूत, अंतर-मंत्रालयी और नियामक समन्वय पर जोर: नड्डा

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार को कहा कि मेडिकल ट्रेवल केवल आर्थिक अवसर नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग और विश्वास निर्माण का माध्यम भी है। मेडिकल ट्रेवल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार अंतर-मंत्रालयी और नियामक समन्वय बढ़ा रही है। सोमवार को ह्याडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2026 के 8वें संस्करण को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए कहा जेपी नड्डा ने कहा कि यह आयोजन सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाने और वैश्विक स्वास्थ्य



सेवा गतिशीलता के भविष्य को सामूहिक रूप से आकार देने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों और हितधारकों को सक्रिय रूप से भाग लेने, सार्थक सहयोग स्थापित करने और एक विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा भागीदार के रूप में भारत द्वारा प्रदान की जाने वाली विशाल क्षमता का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री

(फिक्की) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक माजबूत, गुणवत्तापूर्ण और वैश्विक मानकों के अनुरूप स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण की दिशा में व्यापक सुधार कर रहा है। मेडिकल वेल्यू ट्रेवल भारत की क्लिनिकल उत्कृष्टता, अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानकों और मरीज-केंद्रित देखभाल का प्रतीक है। भारत के कुशल डॉक्टर,

आधुनिक अस्पताल और डिजिटल हेल्थ तकनीकें कार्डियोलॉजी, कैंसर उपचार, अंग प्रत्यारोपण, ऑर्थोपेडिक्स और न्यूरोसाइंस जैसे क्षेत्रों में विश्वस्तरीय सेवाएं दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार विभिन्न मंत्रालयों, नियामक संस्थाओं और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर मेडिकल ट्रेवल इकोसिस्टम को मजबूत बना रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने अपने संबोधन में कहा कि आधुनिक चिकित्सा और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का समन्वय भारत की समग्र स्वास्थ्य दृष्टि को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री योगी का सिंगापुर दौरा : पहले दिन यूपी में निवेश के लिए 20 हजार करोड़ के एमओयू हुए हस्ताक्षरित

एजेंसी (हि.स.)

लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सिंगापुर दौरे के पहले दिन उत्तर प्रदेश को निवेश और कौशल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं। कई बैठकों और निवेशकों के साथ संवाद के बीच कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और कंपनियों ने राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। पहले दिन कुल 19 हजार 877 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर सहमति बनी है। यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन के लिए अहम माने जा रहे हैं। वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने सभी निवेशकों के आवश्यक किया कि उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों को पारदर्शी नीतिगत ढांचा, त्वरित स्वीकृतियां और बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री कार्यालय से सोमवार को मिली

जानकारी के मुताबिक हस्ताक्षरित किए गए समझौता ज्ञापनों में एक बड़ा प्रस्ताव यूनिवर्सल सर्वसेस ग्रुप की ओर से आया है। इसमें ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स पार्क और डेटा सेंटर परियोजनाओं में छह हजार 650 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा है। इन परियोजनाओं से शहरी विकास, औद्योगिक गतिविधियों और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को नई गति मिलने की उम्मीद है। इसी क्रम में गोल्डन स्टेट कैपिटल हस्ताक्षर किए। पहले दिन कुल 19 हजार 877 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर सहमति बनी है। यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन के लिए अहम माने जा रहे हैं। वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने सभी निवेशकों के आवश्यक किया कि उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों को पारदर्शी नीतिगत ढांचा, त्वरित स्वीकृतियां और बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री कार्यालय से सोमवार को मिली



निवेश का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके अतिरिक्त एवीपीएन लिमिटेड ने भी नवीकरणीय ऊर्जा और एपी-पीवी क्षेत्र में दो

हजार 727 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जताई। इन पहलों से उत्तर प्रदेश के हरित ऊर्जा लक्ष्यों को मजबूती मिलेगी।

सरकार के प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री को सिंगापुर यात्रा के पहले दिन निवेश के साथ-साथ कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया

गया। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीटी) को सुदृढ़ करने के लिए आईटीई एजुकेशन सर्विसेज (आईटीईएस) के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी के तहत आईटीईएस शैक्षणिक विकास, बुनियादी ढांचे के उन्नयन, नेतृत्व और क्षमता निर्माण, आईएसक्यू प्रमाणन तथा क्वालिटी एश्योरेंस जैसे क्षेत्रों में परामर्श और तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश की कौशल व्यवस्था को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में बसे भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री योगी ने नए भारत और नए उत्तर प्रदेश की स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरी तस्वीर प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश कभी दलों और कर्प्स के लिए जाना जाता था, वही आज विकास, निवेश, आस्था, औद्योगिक प्रगति और वैश्विक विश्वास का केंद्र बन चुका

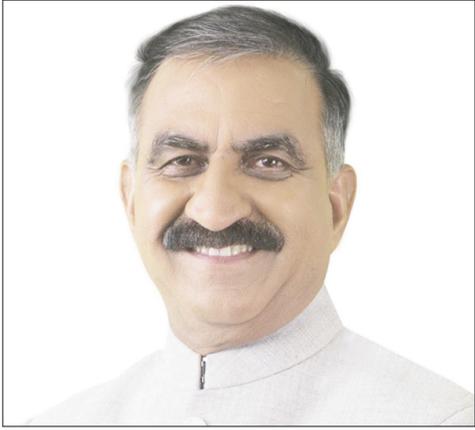
है। अब वह दंगों वाला यूपी नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में न कर्प्स हैं, न दंगा, अब उत्तर प्रदेश में सब चंग है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में नए उत्तर प्रदेश को बदली तस्वीर, विरासत और विकास के संगम तथा कानून-व्यवस्था में आए व्यापक परिवर्तनों को विस्तार से रखा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने उपस्थित सभी लोगों को आगामी होली पर्व की शुभकामनाएं भी दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश आज जिस परिवर्तन का साक्षी है, वह बीते नौ वर्षों की प्रतिबद्धता, सुशासन और दूरदर्श नेतृत्व का परिणाम है। प्रदेश आज कानून-व्यवस्था, निवेश और विकास का मॉडल बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विजन को जमीनी धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करते हुए उत्तर प्रदेश ने ह्यविरासत और प्रस्तुत किया है।

हिमाचल में पहली बार शराब टेकों की ई-नीलामी शुरू, घर बैठे लग सकेंगी ऑनलाइन बोलियां

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश में पहली बार खुदरा शराब टेकों (रिटेल लिक्वर वेड्स) के आवंटन के लिए ऑनलाइन ई-नीलामी प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए इस नई व्यवस्था को मंजूरी देते हुए टेकों का आवंटन पूरी तरह पारदर्शी ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से करने का फैसला लिया है। यह प्रक्रिया 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 की अवधि के लिए लागू रहेगी।

आबकारी विभाग के अनुसार पहले दिन किन्नौर, हमीरपुर और चंबा जिलों के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई। इच्छुक आवेदक विभाग की अधिकारिक वेबसाइट और आबकारी ई-गवर्नेंस पोर्टल पर जाकर सीधे ऑनलाइन बोली में भाग ले सकते हैं। खास बात यह है कि बोलीदाता अपने घर या कार्यालय से ही डिजिटल माध्यम से आवेदन और बोली लगा सकते, जिससे



पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और आसान होने की उम्मीद जताई जा रही है।

किन्नौर, हमीरपुर और चंबा जिलों की शराब इकाइयों के लिए ऑनलाइन आवेदन 23 फरवरी 2026 शाम 6:55 बजे से 26 फरवरी 2026 शाम 6:15

बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। दस्तावेजों की जांच 25 फरवरी शाम 6:30 बजे से 27 फरवरी 2026 शाम 6:55 बजे तक होगी, जबकि नीलामी 28 फरवरी 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी।

दस्तावेजों की जांच 25 फरवरी शाम 6:30 बजे से 27 फरवरी 2026 शाम 6:55 बजे तक होगी, जबकि नीलामी 28 फरवरी 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी।

सिरमौर, ऊना और बद्दी जिलों के लिए आवेदन 24 फरवरी शाम 6:55 बजे से 26 फरवरी शाम 6:15 बजे तक लिए जाएंगे। इन जिलों के दस्तावेज 26 फरवरी शाम 6:30 बजे से 28 फरवरी शाम 6:55 बजे तक जांचे जाएंगे और नीलामी 2 मार्च 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी।

सोलन, कांगड़ा और बिलासपुर जिलों के लिए आवेदन 25 फरवरी शाम 6:55 बजे से 27 फरवरी शाम 6:30 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। दस्तावेजों की जांच 27 फरवरी शाम 6:30 बजे से 2 मार्च शाम 6:55 बजे तक चलेगी और नीलामी 3 मार्च 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी।

मंडी और नरपूर इकाइयों के लिए आवेदन 26 फरवरी शाम 6:55 बजे से 28 फरवरी शाम 6:15 बजे तक जमा किए जा सकेंगे। दस्तावेजों की जांच 28 फरवरी शाम 6:30 बजे से 3 मार्च शाम 6:55 बजे तक की जाएगी, जबकि नीलामी 5 मार्च 2026 को सुबह 9 बजे

से शाम 5 बजे तक होगी।

शिमला और कुल्लू जिलों के लिए आवेदन 27 फरवरी शाम 6:55 बजे से 3 मार्च शाम 6:15 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। इनके दस्तावेज 3 मार्च शाम 6:30 बजे से 6 मार्च शाम 6:55 बजे तक जांचे जाएंगे और नीलामी 7 मार्च 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी।

राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉ. युनुस ने बताया कि सभी आवेदकों के लिए निर्धारित ई-नीलामी पोर्टल पर वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) के माध्यम से पंजीकरण करना अनिवार्य है। उन्होंने संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी है कि वे भाग लेने से पहले आबकारी नीति 2026-27, मानक संचालन प्रक्रिया और उपयोगकर्ता पुस्तिका को ध्यान से पढ़ लें, ताकि प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। ये सभी दस्तावेज विभागीय वेबसाइट और ई-नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं।

कांगड़ा जिला में 478 भूमिहीन परिवारों को उपलब्ध कराई गई जमीन : आयुष मंत्री

एजेंसी (हि.स.)
धर्मशाला

आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल तथा विधि मंत्री यादविंद गोमा ने कहा कि कांगड़ा जिला में पात्र भूमिहीन परिवारों को आवास निर्माण के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने यह बात जिला कांगड़ा में जिला योजना, विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला के सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

आयुष मंत्री यादविंद गोमा ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र भूमिहीन परिवारों को आवास निर्माण के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि लॉन्ग आवेदनों का आवंटन मई माह पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी भूमिहीन परिवार आवास सुविधा से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि कांगड़ा जिला में 478 भूमिहीन परिवारों को आवास के लिए सरकार की ओर से भूमि उपलब्ध कराई गई है।



समीक्षा बैठक के दौरान मनरेगा के अंतर्गत रोजगार उपलब्धता, जॉब कार्ड जारी करने की स्थिति तथा मजदूरी भुगतान की प्रगति पर भी चर्चा की गई। आयुष मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मांग के अनुसार कार्य उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने, उन्हें समय पर श्रेण सुविधा उपलब्ध कराने तथा उनके उत्पादों के विपणन के लिए प्रभावी मंच उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया। यादविंद गोमा ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े पात्र व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए तथा सभी विभाग निर्धारित

लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एंटी-चिद्रा अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए प्रदेश में ह्यचिद्रा सूचना इनम योजना शुरू की गई है और चिद्रा की सूचना देने वालों को इनाम भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में न केवल सख्त प्रवर्तन सुनिश्चित कर रही है, बल्कि नशे से पीड़ित व्यक्तियों की काउंसलिंग, उपचार और पुनर्वास तंत्र को भी मजबूत कर रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि मादक पदार्थ ह्यचिद्रा के उन्मूलन के लिए सक्रिय सहयोग दें तथा 112 नंबर पर कॉल करके या नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दे सकते हैं।

सामुदायिक भवन का किया लोकार्पण, श्री गुरु रविदास जी सभा परिसर में नई सुविधा

एजेंसी (हि.स.)
जम्मू

जम्मू पश्चिम के विधायक अरविन्द गुप्ता ने सोमवार को जम्मू पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के वार्ड संख्या 29 स्थित श्री गुरु रविदास जी सभा में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन कर इसे स्थानीय जनता को समर्पित किया। यह भवन सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए समर्पित रहेगा। उद्घाटन समारोह में सभा समिति के सदस्य, भाजपा के वरिष्ठ नेता, मंडल अध्यक्ष भाजपा रिहाड़ी-बख्शी नगर, पार्टी कार्यकर्ता तथा जम्मू नगर निगम के अधिकारी उपस्थित रहे। स्थानीय निवासियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे क्षेत्र की आधारभूत संरचना में महत्वपूर्ण योगदान बताया। इस अवसर पर विधायक अरविंद गुप्ता ने कहा कि नया सामुदायिक भवन क्षेत्रवासियों को



एक समर्पित मंच प्रदान करेगा जहां विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे विकास कार्य न केवल आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करते हैं बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक परंपराओं को भी सशक्त बनाते हैं। उन्होंने सभा समिति और स्थानीय नागरिकों के सहयोग की सराहना करते हुए आश्वासन दिया कि वार्ड स्तर पर

विकास कार्य उनकी प्राथमिकता में शामिल हैं और जम्मू पश्चिम में नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए आगे भी पहल की जाएगी। सभा समिति के सदस्यों ने विधायक और संबन्धित विभागों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह भवन धार्मिक अनुष्ठानों, सामुदायिक बैठकों, शैक्षणिक गतिविधियों तथा युवाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के कार्यक्रमों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

कठुआ रेलवे स्टेशन के विकास और ट्रेनों के ठहराव बहाली की मांग

एजेंसी (हि.स.)
कठुआ

कठुआ के विधायक डॉ. भारत भूषण ने उत्तरी रेलवे जम्मू मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) विवेक कुमार के साथ बैठक कर कठुआ रेलवे स्टेशन से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए।

विधायक ने डीआरएम को अवगत कराया कि टाटा मूरी, अर्चना एक्सप्रेस और सुवेदारगंज जैसी ट्रेनों का ठहराव कोविड-काल के दौरान कठुआ स्टेशन पर बंद कर दिया गया था, जिसे अभी तक बहाल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे रोजाना आने-जाने वाले कर्मचारियों, यात्रियों तथा अमृतसर स्थित दरबार साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना



करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें ट्रेन पकड़ने के लिए पहले पठानकोट जाना पड़ता है। डॉ. भारत भूषण ने मरोली रोड पर आरपीएफ पुलिस स्टेशन के पास बने अंडरपास की जर्जर स्थिति का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि इस

खराब अंडरपास के कारण कंडी पंचायतों के ग्रामीणों और आईआईटी के केंद्र के औद्योगिक श्रमिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जंगलोट और जसरोटा में रेलवे ट्रैक पर नए अंडरपास के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि यातायात सुचारु रह सके और लोगों को 20-30 मिनट तक लगने वाले जाम से राहत मिल सके। इसके अलावा विधायक ने कठुआ रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के विस्तार, नए पंखे और बैठने की व्यवस्था तथा प्लेटफार्मों के बीच आवाजाही को सुगम बनाने के लिए एक्सेलेटर लगाने की मांग भी की। इस पर डीआरएम विवेक कुमार ने सभी मांगों पर उचित और आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

प्लेटफार्मों के बीच आवाजाही को सुगम बनाने के लिए एक्सेलेटर लगाने की मांग भी की। इस पर डीआरएम विवेक कुमार ने सभी मांगों पर उचित और आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

शिमला में आंगनबाड़ी कर्मियों का प्रदर्शन, आंदोलन तेज करने की चेतावनी

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

राजधानी शिमला में आंगनबाड़ी वर्करज एवं हैल्परज यूनिशन (संबन्धित सीटू) की प्रोजेक्ट कमेटी ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जुटे आंगनबाड़ी वर्कर्स और हैल्परस ने विभाग की कथित उदासीनता के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निदेशक को मांग पत्र सौंपा। प्रदर्शन में यूनिशन से जुड़े कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

प्रदर्शन को संबन्धित करते हुए यूनिशन नेताओं ने आरोप लगाया कि आंगनबाड़ी कर्मियों से भी कठोर अतिरिक्त काम लिया जा रहा है, लेकिन उन्हें जरूरी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं। उनका कहना है



कि कई-कई महीनों तक वेतन न मिलने से कर्मियों को गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नेताओं ने यह भी कहा कि पुराने और खराब मोबाइल फोन, लॉन्ग रिचार्ज भुगतान, स्टेशनरी और किचन सामग्री को कमी, कम दुलाई दर और

प्रोत्साहन राशि में देरी के कारण कर्मचारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। यूनिशन ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाली आंगनबाड़ी कर्मी हर्षा के परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को

करुणामूलक आधार पर नौकरी देने की मांग भी उठाई। इसके अलावा यूनिशन ने साफ कहा कि जब तक नए स्मार्ट फोन या टैबलेट उपलब्ध नहीं कराए जाते, तब तक ऑफलाइन कार्य बंद किया जाएगा। पत्र में सीबीई ईसेंटिव को ऑफलाइन बिल के आधार पर देने, पोषण ट्रेकर से जुड़ी तकनीकी समस्याओं को दूर करने, गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने, वर्दी भत्ता देने, मेडिकल अवकाश और छुट्टियां सुनिश्चित करने तथा आयुष्मान कार्ड में पूरे परिवार को शामिल करने जैसी मांगों को भी प्रमुखता से रखा गया।

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि विभाग ने जल्द सकारात्मक कदम नहीं उठाए तो यूनिशन अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए मजबूर होगी। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति की पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी।

हिमाचल सदन में हुड़दगीयों को पनाह, क्या यही है कांग्रेस का व्यवस्था परिवर्तन: जयराम ठाकुर

एजेंसी (हि.स.)
मंडी

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दिल्ली स्थित हिमाचल सदन में एआई समिट के दौरान प्रदर्शन करने वाले युवकों के ठहरने के मामले में प्रदेश की सुख्ख सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने केंद्र व दिल्ली सरकार से इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जयराम ठाकुर ने सोमवार को मंडी से जारी प्रेस बयान में कड़े शब्दों में प्रहार करते हुए पूछा कि क्या यही मुख्यमंत्री का वह व्यवस्था परिवर्तन है, जिसके तहत उच्च स्थान पर असाधारण तत्व कमरा लेकर हुड़दंग मचा रहे हैं जहां स्वयं मुख्यमंत्री ठहरे हुए थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी लोकप्रिय केंद्र सरकार के खिलाफ साजिश रचने वालों को न केवल हिमाचल सदन में पनाह दी गई, बल्कि वहां पैसें का अवैध लेन-देन तक होने की सूचनाएं हैं, जो राज्य की

छवि के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। नेता प्रतिपक्ष ने इस घटनाक्रम को कांग्रेस के असली चरित्र का प्रमाण बताते हुए कहा कि यह बेहद चिंताजनक है कि सरकारी संपत्ति का उपयोग देश के शीर्ष नेतृत्व के विरुद्ध गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किसके इशारे पर इन प्रदर्शनकारियों को सदन में ठहराया गया और दिल्ली में उन्हें कौन राजनीतिक संरक्षण प्रदान कर रहा था, क्योंकि बिना किसी ऊंचे रसूख के ऐसे संवेदनशील स्थान पर रुकना संभव नहीं है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता का पैसा उन वकीलों पर लुटया जा रहा है जो सरकार के गलत कार्यों को सही ठहराने के लिए मोटी फीस वसूल रहे हैं, जबकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहाल है। उन्होंने मांग की है कि दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां इस मामले की तह तक जाएं कि इन तत्वों के पीछे कौन सी ताकतें सक्रिय थीं।

शिकंजा

पुलिस ने युवक की हत्या कर फरार हुए दो आरोपी गिरफ्तार किए

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

शिमला पुलिस ने बडियारा पुल के पास युवक के ब्लाइंड मर्डर मामले में कुल्लू जिला के कसौल से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एमएसपी शिमला गौरवसिंह ने शिमला में पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि पुलिस थाना चिडगांव में 18 फरवरी को धारा 103, 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसी दिन 112 हेल्पलाइन के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि बडियारा पुल के समीप पम्बर नदी के किनारे चालाका क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। शव से काफी खून बह रहा था तथा मृतक के दोनों हाथ-पैर कपड़े से बंधे हुए थे।

पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद मृतक की पहचान राकेश प्रताप उर्फ सेती राम कामी (36 वर्ष), निवासी डाकाडाम/2 नेपाल के रूप में हुई। वह बडियारा के एक व्यक्ति के बगीचे में मजदूरी करता था। घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक साइंस लैब जुन्गा की टीम और पुलिस डॉग स्कवॉड को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने घटनास्थल से भौतिक और डिजिटल साक्ष्य कब्जे में लिए। हत्या में इस्तेमाल पत्थर और खंजर भी बरामद किए गए। आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और सदिश्यों के फोटो मीडिया के माध्यम से जारी किए गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना वाले दिन मृतक को दो नेपाली मूल के व्यक्तियों के साथ घूमते देखा गया था।



जानकारी के आधार पर पता चला कि 17 फरवरी 2026 को दो सदिश

व्यक्ति मृतक से मिलने बडियारा पहुंचे थे। उन्होंने दिन में मृतक के कमरे में

शराब पी और शाम करीब 7 बजे और शराब पीने के बहाने उसे पम्बर नदी के किनारे किलोका नाला ले गए। वहां मामूली कहासुनी के बाद आरोपियों ने तेजधार हथियार और पत्थरों से हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। आरोपियों ने मृतक का चेहरा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया और उसका मोबाइल फोन गायब कर दिया, ताकि पहचान न हो सके। हत्या के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए और अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए।

डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को आरोपियों के कुल्लू जिला के कसौल और गणौकण क्षेत्र में छिपे होने की जानकारी मिली। प्रवासी मजदूर पंजीकरण रजिस्टर की जांच के बाद आरोपियों की पहचान ललित राणा उर्फ लक्ष्मण राणा (20 वर्ष) पुत्र नैन बहादुर, निवासी भुरपावरी जिला जजरकोट, नेपाल और साहबीर लुवर (21 वर्ष) पुत्र विसे लुवर, निवासी

भुरपावरी जिला जजरकोट, नेपाल के रूप में हुई। दोनों आरोपी कुछ दिन पहले ही गांव देवीधर में मजदूरी के लिए आए थे और घटना के दिन से लापता थे। 22 और 23 फरवरी 2026 की मध्य रात्रि को चिडगांव पुलिस टीम ने कसौल जिला कुल्लू में दबिश देकर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया और उन्हें थाना चिडगांव लाया गया। आरोपियों के कब्जे से मृतक का मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। एमएसपी ने कहा कि पुलिस द्वारा मामले की जांच हर पहलू से की जा रही है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि प्रवासी मजदूरों और किरायेदारों को काम पर रखने या मकान किराये पर देने से पहले नजदीकी पुलिस थाना या चौकी में उनका पंजीकरण अवश्य करावाएं, ताकि भविष्य में किसी भी आपराधिक घटना की स्थिति में समय पर पहचान और कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

संक्षिप्त-समाचार

जेकेपीसीसी किसान विभाग के नेतृत्व में परगवाल में किसानों का प्रदर्शन



जम्मू। जेकेपीसीसी किसान विभाग के प्रदेश अध्यक्ष भारत प्रिय के नेतृत्व में बॉर्डर फार्मर्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले खौड़ उपा-डिवीजन के परगवाल तहसील में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पिछले 72 घंटों से बिजली आपूर्ति ठप रहने के विरोध में किसानों ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (पीडीटी), जिला प्रशासन जम्मू तथा तहसीलदार परगवाल के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि लगातार बिजली कटौती से सिंचाई कार्य, परेल्ड गतिविधियां और सीमावर्ती क्षेत्र का सामान्य जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारत प्रिय ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सीमांत क्षेत्रों के निवासी पहले ही भौगोलिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में मूलभूत सुविधाओं में बाधा अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि खेती के महत्वपूर्ण मौसम में पानी के मोटों के संचालन के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति अनिवार्य है। उन्होंने निकोवाल जैसे सीमावर्ती इलाकों के किसानों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाते हुए कहा कि उन्हें विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। प्रदर्शन के दौरान तहसीलदार परगवाल के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बिजली आपूर्ति की तत्काल बहाली और बार-बार होने वाली कटौती का स्थायी समाधान करने की मांग की गई। ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया कि सिंचाई के लिए उपयोग होने वाले पानी के मोटों के बिजली बिल किसानों से वसूलना अन्यायपूर्ण है, क्योंकि कृषि क्षेत्र पहले ही आर्थिक दबाव झेल रहा है। प्रदर्शन के बाद गांव में बिजली आपूर्ति बहाल होने की सूचना है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि समस्याएं दोबारा उत्पन्न हुईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। भारत प्रिय ने आश्वासन दिया कि सीमांत किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा।

आपदा प्रबंधन, प्राथमिक उपचार और जीवनरक्षक तकनीकों पर 50 प्रतिभागियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण



जम्मू। सरकारी शिक्षा महाविद्यालय नहर मार्ग, जम्मू में 5 दिवसीय सिविल डिफेंस बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सिविल डिफेंस जम्मू के उप निबंधक के पर्यवेक्षण तथा डिप्टी चीफ ऑफिस आर. विजय मंगोतरा के समन्वय से आयोजित किया जा रहा है। शिविर में 50 छात्र-छात्राएं एवं उदात्त सदस्य भाग ले रहे हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को आपातकालीन प्रतिक्रिया, बचाव कार्य, प्राथमिक उपचार, अग्निशमन और जीवनरक्षक तकनीकों का प्रशिक्षण देना है। विशेष रूप से हवाई हमले, प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं के दौरान अपनाए जाने वाले निवारक उपायों की जानकारी भी दी जा रही है। कॉलेज की प्राचार्या डॉ. ज्योति परिहार ने सिविल डिफेंस टीम का स्वागत करते हुए ऐसे उपयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्य वार्डन सिविल डिफेंस, जम्मू परमजीत कुमार ने अपने व्याख्यान में पांच दिवसीय प्रशिक्षण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए सिविल डिफेंस की भूमिका के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक किया। डिप्टी चीफ वार्डन आर. विजय मंगोतरा ने सिविल डिफेंस वार्डन सेवाओं की जिम्मेदारता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सिविल डिफेंस राष्ट्रीय आपदा तैयारी तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है जिसका उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और संकट की घड़ी में त्वरित सहायता प्रदान करना है।

राष्ट्रीय पैरा अल्पाइन स्कीइंग में मंडी का दबदबा: उमेश को स्वर्ण और अतुल को मिला रजत पदक

मंडी। नारकंडा में आयोजित दूसरी राष्ट्रीय पैरा अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में मंडी जिला पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए जिला और प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन किया है। युवा सेवा एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इस प्रतिष्ठित आयोजन में हिमाचल प्रदेश पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के मार्गदर्शन में मंडी के दो जवाना खिलाड़ियों ने कड़े मुकाबलों के बीच शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के परिणामों के अनुसार मंडी के उमेश के खिलाड़ी उमेश कुमार ने अपनी श्रेणी के टैगरी एलनब्ल्यू -9 में उत्कृष्ट तकनीक और अदम्य साहस का परिचय देते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है। वहीं अतुल चौहान ने टैगरी एलनब्ल्यू -4 श्रेणी में अपनी स्टीक स्टिकलस और अथक प्रश्रम के दम पर रजत पदक जीतकर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। इन खिलाड़ियों की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि आत्मविश्वास मजबूत हो और लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण हो, तो कोई भी शारीरिक चुनौती सफलता के मार्ग में बाधा नहीं बन सकती।

सिटी दर्पण

नवोन्मेषक: स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गौता शर्मा
संस्थापक: सतपाल शर्मा

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक भुषिंद्र शर्मा
डॉ. इंद्रजित शर्मा, पंड. भक्तिमणि लिहिंडे, पब्लि. नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, ई.इंटरनेशनल एडव. पंचकुला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1 सेंटर-40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित-160036

सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।

स्थानीय कार्यालय
801/1, सेंटर-40ए, चंडीगढ़।
संपर्क: 7888450261
Email: citydarpn1@gmail.com

संपादकीय

एल मेंचो के खात्मे के बाद इग वर्ल्ड में भूचाल: पाब्लो एस्कोबार से भी खतरनाक था यह सरगना?

मेक्सिको के जलित्स्को न्यू जन्‌रेशन कार्टेल (सी जे एन जी)के प्रमुख नेमेंसियो रूबेन ओसेजोपुरा सर्वेट्स, जिन्हें दुनिया एल मेंचो के नाम से जाना जाता है, को सुरक्षा बलों ने 22 फरवरी 2026 को एक सशस्त्र ऑपरेशन में मार गिराया। यह ऑपरेशन मेक्सिको के पश्चिमी हिस्से में तपल्पा के पास हुआ, जहां मैक्सिकन सैन्य और राष्ट्रीय माओवादी ने संयुक्त कार्रवाई में एल मेंचो को ढेर कर दिया। घटना के तुरंत बाद देश के कई हिस्सों में हिंसा और बदला लेने की प्रतिक्रिया देखने को मिली, जिसमें गाड़ियों में आग, रोड ब्लॉक और सशस्त्र संघर्ष शामिल हैं। इस हमले में सी जे एन जी के कई सदस्यों के साथ-साथ सुरक्षा बलों के घायल होने की भी रिपोर्ट आई। एल मेंचो की मौत न सिर्फ मेक्सिको के लिए, बल्कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए इग व्यापार के खिलाफ संघर्ष में एक बड़ा मोड़ है। अमेरिका ने एल मेंचो को पकड़ने के लिए \$15 मिलियन का इनामी रखा था, जो यह दिखाता है कि उसे दुनिया के सबसे तलाश किए जाने वाले अपराधियों में से एक माना जाता था। इग लॉर्ड्स ऐसे अपराधी होते हैं जो नशीला पदार्थों की तस्करी, वितरण, धन शोधन और हिंसक अपराधों का नेटवर्क चलाते हैं। ये लोग न सिर्फ अपने देश में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की सप्लाई वेन को नियंत्रित करते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कोकीन उपभोक्ता है और इसके लिए ज्यादातर कोकीन लैटिन अमेरिका के कार्टेल्स के माध्यम से आता रहा है। सबसे प्रसिद्ध इग लॉर्ड्स में से एक पाब्लो एंमिलियो एस्कोबार गैरिथिया था, जो कोलंबिया के मेडेलिन कार्टेल का नेता था। 1980 और 90 के दशक में एस्कोबार का कार्टेल अमेरिका और यूरोप को कोकीन की भारी खप

पहुंचाता था। उस समय मेरे अनुमान के अनुसार अमेरिका में जब्त होने वाला 95% कोकीन कोलंबिया में उत्पादित होता था, और एस्कोबार उस सप्लाई का अधिकांश हिस्सा नियंत्रित करता था। एस्कोबार ने अपने इग साम्राज्य से इतनी संपत्ति अर्जित की कि फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया के सातवें सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया था। उनकी शक्ति इतनी बढ़ी कि वह कोलंबिया की राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव डालने लगे थे। पाब्लो एस्कोबार के प्रभाव के साथ-साथ मेक्सिको में मिगुएल एंजेल फेलिक्स गैलार्डों जैसे इग लॉर्ड ने भी अपना दबदबा बनाया। उन्हें 'बॉस ऑफ बॉसेस' कहा जाता था क्योंकि 1980 के दशक में ज्यादातर मैक्सिकन कार्टेल उनके प्रभाव में थे। गैलार्डों के नेतृत्व में मेक्सिको की इग तस्करी को एक संगठित नेटवर्क में बदला गया, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका में इग सप्लाई को मजबूत किया। जोकिन 'एल चापो' गुजमेन मैक्सिको के सिनालोआ कार्टेल का मुख्य चेहरा था। एल चापो ने अमेरिका तक इग सप्लाई और तस्करी के तरीकों पर नियंत्रण रखा था। तीन बार गिरफ्तार होने और जेल से भागने के बावजूद, वह सबसे खतरनाक और प्रसिद्ध इग लॉर्ड्स में से एक रहे। एल मेंचो ने सीजेएनजी को तेजी से विकसित किया और इसे मेक्सिको का सबसे हिंसक और शक्तिशाली कार्टेल बना दिया। सीजेएनजी न केवल कोकीन बल्कि फेटेनाइल, मेंथ और अन्य प्रतिबंधित ड्रग्स की तस्करी में भी शामिल था। एल मेंचो के नेतृत्व में यह संगठन अमेरिका और अन्य देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया था। उनके नेटवर्क में भारी हथियार, ड्रैग, और लड़ाकू क्षमता थी, जिसने इसे केवल एक तस्करी गिरोह से आगे बढ़कर एक सशस्त्र

आतंकवादी संगठन जैसा रूप दे दिया था। अमेरिकी और कनाडाई यहूदियों ने सुरक्षा चेतावनी जारी की थी क्योंकि सीजेएनजी की गतिविधियों से हलचल महसूस की जा रही थी। एल मेंचो की मौत के तुरंत बाद सीजेएनजी के सदस्यों ने मेक्सिको के कम से कम पांच राज्यों में हिंसक प्रतिक्रिया दिखाई। लाग में आग लगाई गई, राजमार्गों को अवरोध किया गया और स्थानीय प्रशासन के लिए स्थिति को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। कई उड़ानें रद्द कर दी गईं और सुरक्षा बलों को स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए तैनात किया गया। हिंसा की लहर ने दिखाया कि इग कार्टेल्स का सत्ता वैकल्पिक शासन पदान जैसे साम्राज्य पैदा कर सकता है, और उनकी गिरावट अक्सर बड़े पैमाने पर प्रतिबंधों और संघर्ष को जन्म देती है। इग लॉर्ड्स ने न केवल लैटिन अमेरिका के देशों को प्रभावित किया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपराध, आतंकवाद और आर्थिक भ्रष्टाचार को भी बढ़ाया है। इनका नेटवर्क बहुदेशीय होता है, जिसमें वित्तीय घोषाधर्मी, मानव तस्करी और हथियारों की आपूर्ति भी शामिल है। अमेरिका को भी इन कार्टेल्स की गतिविधियों के कारण अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना पड़ा है। पाब्लो एस्कोबार से लेकर एल मेंचो तक, इग लॉर्ड्स की कहानी हिंसा, ताकत, पैसे और सत्ता के लिए संघर्ष की है। इन अपराधियों ने न केवल मादक पदार्थों की तस्करी का इतिहास बदला, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक नीतियों को भी प्रभावित किया। एल मेंचो का पतन इस जटिल जाल के खिलाफ एक बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इग व्यापार और उसके नेतृत्व की भूचाल अभी खत्म नहीं हुई है।

वेद और बुद्ध के बीच संवाद की परंपरा

दीपक कुमार द्विवेदी (हि.स)
पश्चिम, क्रिश्चियनिटी और वामपंथी बौद्धिक प्रवृत्तियों में बुद्ध के प्रति जो विशेष आकर्षण दिखाई देता है, उसे केवल आध्यात्मिक या नैतिक कारणों से समझना पर्याप्त नहीं है। यह आकर्षण एक बड़े बौद्धिक परिप्रेक्ष्य में खड़ा है—सृष्टि की अवधारणा, काल-रहित, इतिहास-लेखन की पद्धति, औपनिवेशिक विमर्श और आधुनिक वैचारिक राजनीति के संदर्भ में। इस प्रश्न को भावनात्मक प्रतिक्रिया की बजाय तर्क और संदर्भ के साथ देखना आवश्यक है।

सबसे पहले यह स्पष्ट कर लेना चाहिए कि बौद्ध मत को सनातन वैदिक धर्म से पृथक या विरोधी धारा के रूप में प्रस्तुत करना ऐतिहासिक रूप से दार्शनिक दृष्टि नहीं है। गौतम बुद्ध उस संस्कृतिक और दार्शनिक वातावरण में प्रकट हुए जहां उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म, कर्म और पुनर्जन्म पर गहन विमर्श पहले से चल रहा था। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य आत्मा की अनंतता पर विचार करते हैं। कठोपनिषद में नविकेता मृत्यु के पार के सत्य को जानना चाहता है। खंडोग्य उपनिषद 'तत्त्वमसि' का उद्घोष करता है। भगवद्गीता में आत्मा की अनश्वरता और कर्मफल का सिद्धांत प्रकाशित है। बुद्ध ने कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा को नकारा नहीं। उन्होंने यज्ञकर्म और वेद-प्राप्त्याय की अनिवार्यता पर प्रश्न उठाए, पर उनका चिंतन उसी दार्शनिक धरातल पर विकसित हुआ जिसे सनातन वैदिक परंपरा कह जाता है।

भारतीय दर्शन की परंपरा में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा (वेदान्त), जैन, बौद्ध और चार्वाक जैसे दर्शनों का उल्लेख मिलता है। इसका अर्थ यह है कि भारतीय दार्शनिक संरचना में मतभेद को संवाद के रूप में स्वीकार किया गया, संघर्ष के रूप में नहीं। श्रमण और वैदिक धाराएं एक ही दार्शनिक भूमि की अभिव्यक्तियां थीं।

अब पश्चिमी सृष्टि-दृष्टि पर विचार करें। यूरोप में लंबे समय तक बाइबिल-आधारित कालगणना प्रभावी रही। सत्रहवीं शताब्दी में आयरलैंड के आर्बिशप जेम्स अशर ने बाइबिल की वंशवावृत्तियों के आधार पर सृष्टि की तिथि 4004 ईसा पूर्व निर्धारित की। इस प्रकार मानव इतिहास को कुछ हजार वर्षों की रेखीय समयरेखा में सीमित कर दिया गया। यह दृष्टि एक आरंभ-बिंदु से प्रारंभ होकर क्रमिक विकास और अंत की ओर बढ़ती रेखा पर आधारित थी।

उन्नीसवीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन की 'On the Origin of Species' (1859) प्रकाशित हुई। विकासवाद ने जीवों के क्रमिक परिवर्तन की परिकल्पना दी। डार्विन ने यह कहा कि मनुष्य और आधुनिक वानरों का एक साझा पूर्वज रहा है। लोकप्रिय समझ में यह विचार इस रूप में बैठा कि मनुष्य बंदर से उत्पन्न हुआ। आज भी सामान्य स्तर पर यह प्रश्न उठता है कि यदि ऐसा है तो बंदर अभी भी क्यों हैं? वैज्ञानिक उत्तर यह देता है कि विकास शाखाओं में हुआ, एक सीधी रेखा में नहीं। फिर भी समग्र ढाँचा रेखीय जैविक विकास पर आधारित है।

इसके विपरीत सनातन वैदिक ग्रंथों में सृष्टि की अवधारणा

बहुस्तरीय और चक्रीय है। पुराणों में मानसिक सृष्टि का उल्लेख है—ब्रह्मा द्वारा संकल्प से उत्पत्ति। उसके पश्चात मैथुनिक सृष्टि का क्रम है। यह संकेत करता है कि सृष्टि को केवल भौतिक घटना के रूप में नहीं, बल्कि चेतना और प्रकृति के संयुक्त आयाम में देखा गया। विष्णु पुराण में सृष्टि और प्रलय को वक्र में वर्णित किया गया है। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध में ब्रह्मा के एक दिन की गणना 4.32 अरब वर्ष कही गई है। महाभारत के शांति पर्व में कल्पों और मन्वन्तरों का विस्तार मिलता है। योगवासिष्ठ में असंख्य ब्रह्मांडों की चर्चा है। यहाँ समय अनिर्दिष्ट और चक्रीय है। यदि इस चक्रीय काल-दृष्टि को स्वीकार किया जाए तो सृष्टि को कुछ हजार वर्षों में सीमित करने की धारणा चुनौती के घेरे में आ जाती है। औपनिवेशिक काल में भारत के इतिहास को इसी रेखीय दृष्टि में ढालने का प्रयास हुआ। जेम्स ग्लिव की 'History of British India' (1817) ने भारतीय परंपरा को अंधविश्वासी और अतिक्रियत बनाया। मैक्स मूलर ने वेदों का काल सीमित किया। उन्नीसवीं शताब्दी में आर्य आक्रमण सिद्धांत प्रस्तुत हुआ—यह सिद्ध करने के लिए कि वैदिक संस्कृति स्वदेशी नहीं थी। इससे भारतीय परंपरा की प्राचीनता और निरंतरता पर प्रश्न उठे।

इसी प्रभूमि में 'बौद्ध बनाम ब्राह्मण' का आख्यान विकसित हुआ। कुछ मिशनरी लेखकों और बाद में वामपंथी इतिहासकारों ने यह प्रतिपादित किया कि बौद्ध मत सामाजिक विद्रोह था और वैदिक परंपरा दमनकारी। इससे दार्शनिक निरंतरता को खंडित दिखाया गया और बुद्ध को एक वैकल्पिक नैतिक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया। बुद्ध को 'ईश्वर-निरपेक्ष नैतिक शिक्षक' के रूप में चित्रित करना पश्चिमी बौद्धिकता के लिए अनुकूल था। इससे बाइबिल-आधारित दृष्टि को सीधी चुनौती नहीं मिलती और वामपंथी चिंतन को एक ऐतिहासिक प्रतीक मिल जाता है।

ऐतिहासिक खोज इस सरलीकरण का समर्थन नहीं करती। समाट अशोक के शिलालेखों में वैदिक परंपरा के चिह्नबुद्ध कोई धार्मिक युद्ध का उल्लेख नहीं मिलता। हर्षवर्धन ने बौद्ध विहारों और ब्राह्मणों दोनों को संरक्षण दिया। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने The Buddha and His Dhammal में संकेत किया कि भारत में बौद्ध संस्थानों के पतन में विदेशी आक्रमणों की भूमिका नहीं। नालंदा और विक्रमशिला के विनाश का उल्लेख विभिन्न ऐतिहासिक अभिलेखों में है। अतः बौद्ध मत के लोप को केवल 'ब्राह्मणीय दमन' की कथा में सीमित करना एकान्वेष्टि दृष्टि है।

पश्चिम, क्रिश्चियनिटी और वामपंथी चिंतन में बुद्ध के प्रति विशेष आग्रह का एक कारण आध्यात्मिक आकर्षण हो सकता है, पर उससे अधिक वह वैचारिक सुविधा है जो बुद्ध को सनातन से पृथक प्रस्तुत करने में लिहित है। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि बौद्ध मत उसी दार्शनिक परंपरा की धारा है, कि श्रमण और वैदिक विचार एक ही बौद्धिक भूमि के अंग हैं, तो यह कृत्रिम द्वंद समाप्त हो जाता है।

बुद्ध और सनातन के बीच विभाजन स्थापित करना ऐतिहासिक जटिलता को सरल बनाता है। समस्या बुद्ध में नहीं है, समस्या उस व्यख्या में है जो उन्हें सनातन के विरुद्ध खड़ा करती है। जब सृष्टि-दृष्टि, काल-रहित और दार्शनिक निरंतरता के संदर्भ में विचार को देखा जाता है, तो स्पष्ट होता है कि दोनों को अलग कर-के देखना ही मूल क्षम है।

(लेखक, स्तम्भकार हैं।)

संपादकीय/धर्म दर्पण

27 साल के लंबे अंतराल के बाद दिल्ली में रेखा गुप्ता की अगुवाई में बनी भाजपा सरकार ने साल भर के बुनियादी भविष्य की विकसित दिल्ली की ठोस शासन (20 फरवरी,2026 को सरकार के एक साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंत्रिमंडल के अपने सभी सहयोगियों के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में अपनी सरकार का रिपोर्ट दें काई जारी किया। इस मौके पर पहला कदम बदलाव का, एक साल विकास का, नाम से एक बुकलेट भी जारी की गई। इसमें दावा किया गया कि दिल्ली की भाजपा सरकार ने बहाने बनाने के बजाव कड़ी मेहनत करके भविष्य की जरूरतों को हिसाब से विकसित दिल्ली बनाने के लिए हर दिन काम किए। 365 दिन में 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर(डिस्पेंसरी) बने, इसकी संख्या इस साल साठहत्तर को 1998 में शीला दीक्षित की अगुवाई बनी कांग्रेस सरकार ने और आगे बढ़ाया। दिल्ली के मूलभूत ढांचे के विकसित करने की सर्वाधिक श्रेय शीला दीक्षित के जाता है। पूरी दिल्ली में काम हुए। दिल्ली फ्लाईओवर का शहर बना। असंभव हो चुके अंदोलन को मुक्त उपाचर के लिए आयुष्मान योजना न केवल दिल्ली में लागू किया गया। अब तक इस योजना में सात सत्रस से ज्यादा लोग पंजीकरण करकर इसका लाभ उठा रहे हैं। सुग्रीव रिस्तरियों के लिए सात सौ करोड़ का बजट जारी किया गया है। दिल्ली में देश का सर्वाधिक न्यूनतम वेतन 22411 रुपये प्रति महीना लागू किया गया। कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए 500 पालन केंद्र खोले गए हैं। परिवहन क्षेत्र में चार हजार से अधिक ई-बसें चलाई जा रहा है। नौ हजार से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। नई ईवी नीति, ई- बाइक, ई-टेक्सी को बढ़ावा देने के अलावा दिल्ली-अंधी छोर तक सार्वजनिक से वाहन को पहुंचाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। वैसे अभी सरकार के हाई कोर्ट के हलफनामे के हिसाब से 11 हजार बसों को सड़क पर लाने की भी चुनौती है। यमुना साफ करने के लिए बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। 137 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में से 28 को अपग्रेड किया गया है। नौ पर काम चल कहा है। 12 पार संयंत्र बनेगे। दिल्ली को वायु प्रदूषण से मुक्त करने से लेकर दिल्ली के मूलभूत ढांचे को विकसित करने से लेकर दिल्ली को आधुनिकतम



मनोज कुमार मिश्र (हि.स)

सुविधाओं से युक्त शहर बनाने के प्रयास के लिए दिल्ली सरकार केन्द्र की सरकार के सहयोग से दिन-रात काम कर रही है। साल 1993 में दिल्ली में ना प्रशासनिक ढांचे में विधानसभा बनने पर हुए पहले चुनाव में भाजपा की सरकार बनी। पांच साल में तीन मुख्यमंत्री बदलने के बावजूद उस सरकार ने कई ठोस काम किए। 1998 में शीला दीक्षित के जल में राज्य की तरह दिल्ली को हिसाब मिला। दिल्ली सरकार ने अपने अधिकार बढ़ाकर बिजली बंद बनाकर बिजली का उत्पादन बढ़ाया। नाट स्कूल कालेज ही नहीं नया विश्वविद्यालय बनाया गया। नाट अस्पताल बने और बड़ी संख्या में दिल्ली के हर कोने में निर्माण कार्य हुए। दिल्ली मेट्रो की नींव रखी गई।1984 के सिख दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने के प्रयास हुए। इस सिलसिले को 1998 में शीला दीक्षित की अगुवाई बनी कांग्रेस सरकार ने और आगे बढ़ाया। दिल्ली के मूलभूत ढांचे के विकसित करने की सर्वाधिक श्रेय शीला दीक्षित के जाता है। पूरी दिल्ली में काम हुए। दिल्ली फ्लाईओवर का शहर बना। असंभव हो चुके अंदोलन को मुक्त उपाचर के लिए आयुष्मान योजना न केवल दिल्ली में लागू किया गया। अब तक इस योजना में सात सत्रस से ज्यादा लोग पंजीकरण करकर इसका लाभ उठा रहे हैं। सुग्रीव रिस्तरियों के लिए सात सौ करोड़ का बजट जारी किया गया है। दिल्ली में देश का सर्वाधिक न्यूनतम वेतन 22411 रुपये प्रति महीना लागू किया गया। कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए 500 पालन केंद्र खोले गए हैं। परिवहन क्षेत्र में चार हजार से अधिक ई-बसें चलाई जा रहा है। नौ हजार से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। नई ईवी नीति, ई- बाइक, ई-टेक्सी को बढ़ावा देने के अलावा दिल्ली-अंधी छोर तक सार्वजनिक से वाहन को पहुंचाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। वैसे अभी सरकार के हाई कोर्ट के हलफनामे के हिसाब से 11 हजार बसों को सड़क पर लाने की भी चुनौती है। यमुना साफ करने के लिए बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। 137 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में से 28 को अपग्रेड किया गया है। नौ पर काम चल कहा है। 12 पार संयंत्र बनेगे। दिल्ली को वायु प्रदूषण से मुक्त करने से लेकर दिल्ली के मूलभूत ढांचे को विकसित करने से लेकर दिल्ली को आधुनिकतम

अंकुश लगाना नहीं चाहता है। दिल्ली का अपना कुछ नहीं है। मौसम से लेकर बिजली-पानी के लिए दिल्ली पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है। दिल्ली की सड़कों भी एक सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। शीला दीक्षित ने भी सड़क के ऊपर सड़क (डबल डेकर रोड) बनाने की योजना बनाई थी, उस पर अमल रेखा गुप्ता सरकार करने वाली है। सड़कों से वाहनों की भीड़ कम

होना कठिन हो गया है। पेरिफेरियल सड़कों के अलावा चार सौ किलोमीटर मेट्रो चलाये और दिल्ली से मेट्रो के लिए नमो भारत रेल शुरु होने आदि के बावजूद सड़कों पर भीड़ लगातर बढ़ रही है। केन्द्र सरकार ने दो और रास्तों पर नमो भारत रेल चलाने की घोषणा की है।

पिछली सरकार से विपरीत इस सरकार ने फटाफट मेट्रो के अगले चरणों को मंजूरी दी है। नाट चरणों के लिए बजट भी आवंटित किए गए हैं। मेट्रो के विस्तार से सड़कों पर से वाहनों की भीड़ कुछ कम होने की उम्मीद जगी है। लोको निर्माण विभाग की 1400 किलोमीटर सड़कों में से पहले साल में 550 किलोमीटर सड़कों की वाल-टू-वाल कारपोर्टिंग का काम पूरा हो गया है। नंद नगरी फ्लाईओवर जगत को समाप्त कर दिया गया है। मुकद्दबा चौक अंडर पास मार्च तक और बारापूला का अगला चरण जून तक पूरा होने के दावे किए गए हैं। 40 नाट फुट

1.75 लाख बच्चियों के भुगतान की पहले चरण में तीस हजार बच्चियों के स्नाते में 90 करोड़ रुपये भेजे गए। अब लाइली योजना के बाद ज्यादा पैसा देने वाली लखपति योजना को लागू करने की योजना है। दिल्ली को वायु प्रदूषण से मुक्त करने के लिए वायु प्रदूषण शमन योजना बनाई गई है। सरकार का फोकस दिल्ली की साफ सफाई पर है, इसमें उसे काफी सफलता मिली है। पहला बरखात ऐसा बीता जिसमें बहुपर्यटित मिंटो रोड को लंबे समय तक बंद न करना पड़ा। पिछले दिनों सरकार ने मेधावी छात्र-छात्राओं को सरकार लैटुएट देने और ओलंपिक आदि जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि बढ़ाई । राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी

करने वाले खिलाड़ियों को बीस लाख रुपये की सहायता दी जा रही है। दिल्ली में खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि दिल्ली में हर रोज निकलने लावे 11 हजार मीट्रिक टन कचरे का निबटान करने की व्यापक योजना करने से कूड़े के नाए पहाड़ बनेगे। इतना ही नहीं कूड़े के पहाड़ों से भी दिल्ली को जल्दी ही निजात मिल जागी।

आम आदमी पार्टी के हारने के कई कारणों में एक काम यह माना जाता है, कि उसकी सरकार ने दिल्ली की मूल ढांचे की बेहतरी के लिए ठोस काम नहीं किए। लेकिन उसके कुछ अच्छे कामों में से एक काम निजी स्कूलों के फीस पर नियंत्रण रखना था। आआपा सरकार जिते ही निजी स्कूलों ने बेहिसाब फीस बढ़ा दी। भाजपा सरकार को इसके विरोध में सड़कों पर उतरे लोगों को शांत करने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने पड़े। सरकार ने फीस रेगुलेशन बिल विधानसभा में पास करके निजी स्कूलों पर लगाम लगाई। इस साल 44 करोड़ रुपये की छत्रवृति बांटी गई। इस सरकार के सामने यमुना को साफ करने की बड़ी चुनौती है। सरकार बनते ही मुख्यमंत्री ने यमुना की अरती शुरू कराई और यमुना को साफ करने का संकल्प लिया। दिल्ली जल बोर्ड में इसके लिए कई योग्य अधिकारी तैनात किए गए। इस साल यमुना से और दिल्ली के नालों से 22 लाख मीट्रिक टन सिल्ट निकाली गई। यमुना में गिरने वाले नालों को टैप (गंदगी गिरने से रोकने) करने के लिए ड्रेन सर्वे कराए गए। पुराने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करने और 12 नाट लगाने का काम हो रहा है। यमुना का जल अनवरत बढ़ता रहे, इसके लिए पड़ोसी राज्यों से समन्वय का काम किया जा रहा है। दिल्ली को भरोसा है कि इसका अंतर आने वाले समय में दिखेगा।

बावजूद इसके इस सरकार के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। सबसे बड़ी चुनौती तो दिल्ली में आने काम से बड़ी लकीर खींचने की है। भाजपा दिल्ली में विधानसभा बनने के बाद हुए पहले चुनाव यानी 1993-98 के बाद लगातार दिल्ली की सरकार से बेदखल होती रही है। उसे अपने काम के बल पर दिल्ली में लगातार चुनाव जीतने लायक माहौल बनाया है। सालों दिल्ली की सत्ता में रही कांग्रेस हाशिये पर है। दिल्ली पर दस साल राज करने वाली आआपा भी ढलान पर है। संयोग से केन्द्र, दिल्ली और दिल्ली नकार निगम के सत्ता में भाजपा काबिज है। ऐसे में दिल्ली की भाजपा सरकार के लिए दिल्ली की बहुशासन प्रणाली बाधा नहीं बन रही है। अभी तो शुरुआत है आने वाला समय बताओ कि दिल्ली सरकार अपने लक्ष्य में कितना सफल हो पाई।

(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

नई दिल्ली घोषणा से कृषि क्रांति तक भविष्य की वैश्विक धुरी एआई

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने विश्व समुदाय को यह स्पष्ट संकेत दे दिया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत अब नीति निर्धारण और वैश्विक दिशा तय करने वाला देश बन चुका है। 89 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी तथा 88 देशों द्वारा हस्ताक्षरित नई दिल्ली घोषणा ने भारत के मानव-केन्द्रित एआई दृष्टिकोण को जब अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रदान की, तब इसके साथ यह भी थय हो गया कि भारत अब एआई क्रांति में आर्थिक, सामाजिक और नैतिक आयामों को समेटने वाला देश बनने जा रहा है।

दरअसल, नई दिल्ली घोषणा का मूल दर्शन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस विचार में निहित है, जिसमें एआई को मानव कल्याण का साधन माना गया है।

केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि यह घोषणापत्र सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना से प्रेरित है। इसका उद्देश्य एआई संसाधनों और उसके लाभों को कुछ देशों या कंपनियों तक सीमित रखने के बजाय पूरी मानवता तक पहुंचाना है। घोषणा में सात प्रमुख स्तंभों को आधार बनाया गया है, एआई संसाधनों का लोकतंत्रीकरण, आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई, सुरक्षित और भरोसेमंद एआई, विज्ञान के लिए एआई, सामाजिक समावेशन, मानव पूंजी विकास तथा लचीली और ऊर्जा-कुशल प्रणालियां। यहां यह ढांचा वैश्विक सहयोग की नई संरचना प्रस्तुत करता हुआ दिखा है, जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करते हुए सझा प्रगति को प्राथमिकता दी गई है।

700 अरब डॉलर तक पूंजीगत व्यय की तैयारी



डॉ. मयंक चतुर्वेदी (हि.स)

को और मजबूत किया। ओपनएआई के सैम ऑल्ट्रैमैन, अल्फाबेट के सुंदर पिचाई, गैर्रोपिक के डारियो अमोर्देई और गुगल डीपमाइंड के डेमिस हासाबिस जैसे वैश्विक नेता इस आयोजन में शामिल हुए। निश्चित ही यह भागीदारी संकेत है कि भारत अब वैश्विक तकनीकी विमर्श का केंद्र बन चुका है। अमेरिका और भारत के बीच पैक्स सिलिका समझौते ने सिलिकॉन आधारित तकनीकों की वैश्विक आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित करने के सहयोग को नया आयाम दिया है। भारत द्वारा 18 अरब डॉलर की सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी देना इस रणनीतिक दृष्टि का आधार है।

एआई के संदर्भ में भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका समावेशी दृष्टिकोण है। यहां एआई को केवल कॉर्पोरेट लाभ का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का उपकरण माना जा रहा है। इसका सबसे सशक्त उदाहरण कृषि क्षेत्र में दिखाई देता है। इस संदर्भ में मुंबई में आयोजित AI4Agri 2026 सम्मेलन को देखा जा सकता है, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट कहा कि भारत की अगली कृषि क्रांति एआई संचालित होगी।

इंडिया एआई मिशन, जिसका बजट 10,372 करोड़ रुपये है,

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में मंत्रिमंडल द्वारा पंजाब सरकार खाद्य कार्यक्रम के ऐतिहासिक फैसले को हरी झंडी, एन.एफ.एस.ए. के तहत 40 लाख परिवारों को गेहूं, दाल, चीनी, तेल और नमक मिलेगा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब मंत्रिमंडल ने जनकल्याण सेवाओं के विस्तार और वित्तीय मजबूती प्रदान करते हुए एक अहम फैसले के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.) के अंतर्गत आने वाले 40 लाख परिवारों को गेहूं, दाल, चीनी, तेल और नमक उपलब्ध कराने के लिए ऐतिहासिक पंजाब सरकार खाद्य कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है, जो पंजाब के इतिहास का सबसे व्यापक खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के लिए आबकारी राजस्व में 12,800 करोड़ रुपये का लक्ष्य भी निर्धारित किया है, जिसके तहत अगले पांच वर्षों में जनकल्याण योजनाओं को मजबूत करने के लिए राजस्व संग्रह को दोगुना करने का अनुमान है।

खाद्य कार्यक्रम के साथ-साथ कैबिनेट ने सरकारी भूमि पर खेती करने

वाले बाद प्रभावित किसानों को एकमुश्त मुआवजा देने के निर्णय को मंजूरी दी, सरकारी विभागों और सार्वजनिक संस्थानों के लिए एकमुश्त निपटान योजना को 30 जून, 2026 तक बढ़ाया और वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए पारदर्शी इनाम नीति को स्वीकृति दी।

सरकार ने यह भी घोषणा की कि 16वां पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 6 मार्च से 16 मार्च तक आयोजित किया जाएगा और राज्य का बजट 8 मार्च को प्रस्तुत किया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 361 स्टाफ नर्सों के पद पुनः बहाल किए जाएंगे तथा कोविड वालंटियर्स को भर्ती में आयु सीमा में छूट और अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे, जो भगवंत सिंह मान सरकार के तहत जनकल्याण, वित्तीय एकजुटता और प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़े कदम का संकेत है।

आज यहां यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस जनपक्षीय पहल के तहत



सरकार राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 (एन.एफ.एस.ए.) के तहत पंजीकृत लाभार्थियों को गेहूं के साथ-साथ चीनी, दाल, सरसों का तेल और नमक वितरित करेगी। इससे राज्य के लोगों, विशेषकर समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों, जिनमें 40 लाख एन.एफ.एस.ए. कार्डधारक शामिल हैं, को बड़ी राहत मिलेगी, जिससे वे अपने बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा

सकेंगे। इस कदम से अप्रैल महीने से सुदृढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री की आपूर्ति से आम आदमी को बड़ा लाभ होगा। मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य की आबकारी नीति को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 12,800 करोड़ रुपये का आबकारी राजस्व एकत्र करने

का लक्ष्य रखा गया है, जो कि वित्त विभाग द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित 11,200 करोड़ रुपये के संशोधित लक्ष्य की तुलना में 1,600 करोड़ रुपये (12.5%) की वृद्धि दर्शाता है। आबकारी राजस्व, जो वर्तमान सरकार के कार्यकाल की शुरुआत में लगभग 6,200 करोड़ रुपये था, के पांच वर्षों की अवधि में दोगुना होने का अनुमान है। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025 में भारी वर्षा

के दौरान आई बढ़ से फसलों को हुए नुकसान के लिए उन किसानों (जो सरकारी भूमि पर खेती कर रहे हैं) को मुआवजा देने की भी मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के अनुसार जिन किसानों की वर्ष 2025 की विशेष गिरदावरी के दौरान फसल नुकसान का आकलन किया गया था, लेकिन उन्हें फसल मुआवजा नहीं दिया गया था क्योंकि उनकी गिरदावरी 15 सितंबर, 2015 के माननीय हाई कोर्ट के

निर्देशों और 25 सितंबर, 2015 के राज्य सरकार के पत्र के अनुपालन में सरकार के पक्ष में बदल दी गई थी, उन्हें भी फसल मुआवजा दिया जाएगा। यह मानवता के आधार पर एकमुश्त समाधान के रूप में किया जाएगा और किसी भी प्रकार से किसी की भी स्वामित्व अधिकार प्रदान नहीं करेगा। इस हेतु जहां भी 25 सितंबर, 2015 से पहले खसरा गिरदावरी में दर्ज व्यक्ति अभी भी भूमि की खेती कर रहा है या उसके कानूनी वारिस भूमि की खेती कर रहे हैं, मुआवजा उस व्यक्ति या उसके कानूनी वारिसों को दिया जाएगा, जैसा भी मामला होगा। यदि कब्जे में कोई परिवर्तन पाया जाता है जो वर्ष 2015 के राजस्व रिकॉर्ड के अनुरूप नहीं है, तो कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। सरपंच, नंबरदार और पटवारी की समिति इस संबंध में पुष्टि करेगी और किसानों को मुआवजा वितरित करने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मंत्रिमंडल ने 13 मार्च, 2025 को अधिसूचना की गई एकमुश्त निपटान योजना (ओ.टी.एस.) को 31 दिसंबर, 2025 से बढ़ाकर 30 जून,

2026 तक लागू रखने की मंजूरी दे दी है। यह विस्तार केवल उन प्लॉटों पर लागू होगा जो सरकारी विभागों/सार्वजनिक संस्थानों को आवंटित किए गए हैं तथा उन आवंटियों पर भी लागू होगा जिन्होंने 7 मई, 2025 की नीति के तहत प्लॉटों की बहाली के लिए अपीलें दायर की थीं और जो ओ.टी.एस. योजना के अंतर्गत अपने बकाया का निपटान करने के पात्र थे तथा जिनके प्लॉट पी.एस.आई.सी. के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा बहाल किए गए हैं। उन्हें 13 मार्च, 2025 से 30 जून, 2026 तक ओ.टी.एस. योजना के तहत ब्याज सहित अपने बकाया का निपटान करने की अनुमति होगी। मंत्रिमंडल ने वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पंजाब की इनामी नीति को भी मंजूरी दे दी है। इस कदम का उद्देश्य इनाम देने के लिए एक पारदर्शी और सुव्यवस्थित प्रक्रिया को संस्थापित रूप देना है, ताकि सूचना देने वालों को प्रोत्साहित किया जा सके और वांछित अपराधियों को पकड़ने में कानून लागू करने वाले जवानों के प्रयासों को मान्यता दी जा सके।

पंजाब सरकार द्वारा जल्द करवाई जाएगी एन.आर.आई. मिलनी: डॉ. रवजोत सिंह

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब सरकार द्वारा जल्द ही जिला वार एन.आर.आई. मिलनियां आयोजित की जाएंगी। यह जानकारी आज यहां एन.आर.आई. मामलों से संबंधित विभागीय उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने दी।

डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा विदेशों में बसे पंजाबी एन.आर.आई.ज की समस्याओं को हल करने के लिए एन.आर.आई. मिलनियां लगातार आयोजित की जा रही हैं और इसी दिशा में चालू वर्ष के दौरान राज्य के प्रत्येक जिले में एन.आर.आई. मिलनियां करवाई जाएंगी। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य एन.आर.आई.ज को सामने आने वाली



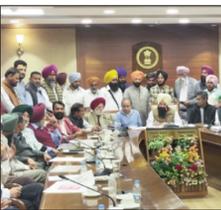
समस्याओं का समाधान उनके पास पहुंचकर करना है ताकि उन्हें सरकारी दफ्तरों के अनावश्यक चक्कर न काटने पड़ें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एन.आर.आई.ज के मामले और शिकायतें निर्धारित समय के अंदर हल की जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार

उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने एन.आर.आई.ज की पंजाब में पड़ी जमीन-जायदाद के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित बनाने के लिए पुख्ता प्रबंध किए हैं। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि एन.आर.आई.ज सभा के चुनाव जल्द करवाए जाएं और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई को तेजी से पूरा किया जाए।

इस मौके पर एन.आर.आई. विभाग के सचिव श्री वी.ए. जादे, डिवीजनल कमिश्नर जालंधर तथा सचिव सुचना एवं लोक संपर्क विभाग श्री रामवीर, विशेष सचिव एन.आर.आई. श्रीमती अमनदीप कौर, ए.डी.जी.पी. एन.आर.आई. श्री आर. के. जैस्वाल, अतिरिक्त सचिव एन.आर.आई. श्री आर. बी.एस. बराड़ और ए.आई.जी. श्री अजिंदर सिंह उपस्थित थे।

जसवीर सिंह गढ़ी ने पंजाब के समूह एस.सी.कर्मचारी संगठन की मुश्किलें सुनी

चंडीगढ़। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति कमिशन के चेयरमैन श्री जसवीर सिंह गढ़ी ने अनुसूचित जाति वर्ग के साथ सम्बन्धित पंजाब की एस.सी. कर्मचारी संगठन की समस्याओं और संवैधानिक अधिकारों को लागू करवाने में आ रही परेशानियों को हल करवाने के लिए पंजाब भवन, चंडीगढ़ में विशेष मीटिंग की अध्यक्षीय की गई। इस मीटिंग में राज्य के ज्यादातर एस.सी. कर्मचारी संगठन ने हिस्सा लिया। संगठन के प्रतिनिधियों ने मीटिंग दौरान आरक्षण/ प्रतिनिधिता



सम्बन्धित पंजाब में लागू नियमों का पुन मूल्यांकन करने की मांग करते कहा कि पंजाब राज्य में आरक्षण नीति 1971 के जनगणना अनुसार तय की गई थी, जिसमें 50 साल बीतने के बावजूद की कोई मूल्यांकन नहीं किया गया जबकि पंजाब राज्य में दलित आबादी 38 फीसद से ज्यादा हो गई है। इसके साथ ही इन नेताओं द्वारा 85वीं संवैधानिक संशोधन लागू करने, 10- 10- 2014 को जारी किए गए गैर संवैधानिक पत्र को वापिस लेने रोस्टर रजिस्ट्ररों और बैकलाग के साथ सम्बन्धित भर्ती के साथ सम्बन्धित मामलों को ठठायी गया और कमिशन से मांग की गई कि इस सम्बन्धित जल्द कार्यवाही करके इन मसलों को हल करवाया जाए। कर्मचारी संगठनों ने कच्चे कर्मचारियों का भी मुद्दा उठाते कमिशन से मांग की कि इनकी सेवाओं को रेगुलर करवाने के लिए उद्यम किए जाएं। आज की इस बैठक में स.जसवीर सिंह पाल, स.अवतार सिंह कैथ, स. अमरीक सिंह बंगड, स.कृष्ण सिंह और कई अन्य उपस्थित थे।

विदेशों में बैठे पंजाबियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार विदेशों में बसे पंजाबी एन.आर.आई.ज की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत में जमशेदपुर के बाद टाटा स्टील का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट अब पंजाब में : भगवंत सिंह मान

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज यहां कहा कि मार्च से लुधियाना में टाटा स्टील के मैनुफैक्चरिंग प्लांट के कार्यशील होने से पंजाब में उद्योग को बड़ा हाँसला मिलेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह प्रोजेक्ट राज्य की प्रगतिशील नीतियों और मजबूत शासन ढांचे में वैश्विक उद्योग के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

टाटा स्टील के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करते हुए, जिसमें उपाध्यक्ष (लॉग प्रोडक्ट्स) आशीष अनुपम और कॉर्पोरेट मामलों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल थे, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि टाटा स्टील शुप दुनिया के अग्रणी स्टील निमाताओं में से एक है, जिसकी कच्चे स्टील की वार्षिक क्षमता लगभग 34 मिलियन टन है और दुनिया के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में



इसका मजबूत स्थान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टाटा स्टील लिमिटेड लुधियाना की हाई-टेक वेल्डिंग के निकट रीवार मिल के साथ 0.75 एम.टी.पी.ए. इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस आधारित स्टील-मेकिंग सुविधा स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि 115 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में शुरू में लगभग 2,600 करोड़ के निवेश का अनुमान था, जो अब बढ़कर 3,200 करोड़ हो गया है। इस प्लांट से लगभग 2,500 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र के औद्योगिक

और से निभाई गई सक्रिय भूमिका को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने इस मेगा प्रोजेक्ट के निर्माण और संचालन को समर्थन बढ़ाकर सुनिश्चित किया है, जो पंजाब की उद्योग-समर्थक नीतियों और सक्रिय शासन ढांचे को दर्शाता है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत को राज्य के लिए गौरव की बात बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह जमशेदपुर के बाद भारत में टाटा स्टील का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट है और पंजाब में कंपनी के सबसे बड़े निवेश को दर्शाता है। निरंतर औद्योगिक विस्तार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने प्रोजेक्ट के सफल संचालन और पारदर्शिता में और विस्तार के लिए टाटा स्टील को पूरा समर्थन और सहयोग देने का भरोसा दिया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

दोआबा में फसल विविधता के लिए पंजाब के विधायकों की पहल, मार्केटिंग सहयोग और बड़े मुनाफे का आश्वासन

राणा गुरजीत सिंह, राणा इंद्र प्रताप सिंह द्वारा शाहकोट में कसावा खेती को प्रोत्साहन

सिटी दर्पण संवाददाता
शाहकोट (गांव मलसियां)

फसल विविधता और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कपूरथला से विधायक राणा गुरजीत सिंह और सुल्तानपुर लोधी से विधायक राणा इंद्र प्रताप सिंह ने आज शाहकोट के निकट गांव मलसियां का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों से मुलाकात कर पारंपरिक पानी-गहन फसलों के स्थान पर कसावा की खेती को एक लाभकारी विकल्प के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया।

किसानों की विशाल सभा को संबोधित करते हुए राणा गुरजीत सिंह ने पंजाब में तेजी से गिरते भूजल स्तर पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, हमें अपना भूमिगत पानी बचाना होगा, जो हर वर्ष लगभग एक मीटर की दर से नीचे जा रहा है। अपने पिछले प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, मैं स्वयं को एक किसान मानता हूँ। मेरा कार्य केवल

विधानसभा में लोगों का प्रतिनिधित्व करना ही नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर उनकी भलाई के लिए काम करना भी है। वर्ष 2019 में जब मजदूरों की भारी कमी थी, तब मैंने पी.ए.यू. के सहयोग से डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस (डफ) को प्रोत्साहित किया। यह तकनीक 2007-08 में विकसित की गई थी। उन्होंने बताया कि इस पद्धति से 30 प्रतिशत तक पानी की बचत हुई, लेकिन बाद में धान उत्पादक फिर पारंपरिक तरीके पर लौट गए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हम लगभग 16 बिलियन क्यूबिक फीट अतिरिक्त भूजल निकाल रहे हैं, जिससे पंजाब का कीमती प्राकृतिक खजाना समाप्त हो रहा है।

किसानों को नई फसलों की ओर कदम बिसाल के लिए प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि मार्केटिंग की चिंता अक्सर फसल विविधता में बाधा बनती है। जब भी हम नई फसल की बात करते हैं, किसान तुरंत उसकी खरीद-फरोख



के बारे में पूछते हैं। मैं उनकी चिंता समझता हूँ। इसलिए मैंने मानसूनी मक्का को न केवल प्रोत्साहित किया, बल्कि उसकी खरीद का आश्वासन भी दिया और अगले वर्ष भी इस वचन पर कायम रहूंगा, उन्होंने कहा।

कसावा की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने इसे ग्लूटेन-मुक्त और कीट-प्रतिरोधी फसल बताया, जिसे कम देखभाल की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा, कसावा को दो इंच गहराई और 3-6 इंच की दूरी पर लगाया जाता है।

प्रति एकड़ लगभग 5,000 पौधे लगाए जा सकते हैं, जिनसे प्रत्येक पौधे से लगभग पांच किलोग्राम उत्पादन मिलता है। इस प्रकार प्रति एकड़ लगभग 250 किलोग्राम प्रति एकड़ संभव है। उन्होंने आगे कहा, पहले तीन महीनों में कुछ देखभाल और केवल एक खरपतवारनाशक छिड़काव की आवश्यकता होती है। इसके बाद फसल सात से नौ महीनों में तैयार हो जाती है। उन्होंने बताया कि कसावा दोमट और बलुई दोमट मिट्टी में अच्छी पैदावार देती

है, जिससे यह दोआबा क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। युद्ध विश्वास है कि दोआबा के मेहनती किसान कसावा को भी उतनी ही सफलता देंगे जितनी उन्होंने मक्का और चुकंदर को दी है। मक्का की पैदावार 20 क्विंटल से बढ़कर लगभग 50 क्विंटल प्रति एकड़ हो गई है, जबकि चुकंदर की खेती 15,000 एकड़ तक फैल चुकी है और 500 क्विंटल प्रति एकड़ उपज दे रही है, उन्होंने कहा। आर्थिक दृष्टि से कसावा की लाभप्रदता पर जोर देते हुए राणा गुरजीत सिंह ने कहा, वर्तमान में कसावा लगभग 15 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही है, जिससे प्रति एकड़ लगभग 2.5 लाख रुपये की आय संभव है। उचित मार्केटिंग होने पर कीमत 20 रुपये प्रति किलोग्राम से भी ऊपर जा सकती है। आलू जैसी फसलों की तुलना में, जहां कीमतों में उतार-चढ़ाव से नुकसान होता है, कसावा स्थिर और अधिक मुनाफा देती है। उन्होंने कम से कम 20 किसानों से

अपील की कि वे एक-एक एकड़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत करें। मार्केटिंग संबंधी आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा, यदि मैं मक्का का समर्थन कर सकता हूँ तो कसावा का भी करूंगा। मार्केटिंग कोई समस्या नहीं होगी। खरीद और प्रोसेसिंग सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है। कटाई के 48 घंटे के भीतर उत्पाद को फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाएगा, जहां इसे सुखे पाउडर के रूप में प्रोसेस किया जाएगा, और हम यह सुविधा उपलब्ध कराएंगे। राणा इंद्र प्रताप सिंह ने कसावा के औद्योगिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, मक्का में लगभग 58 प्रतिशत स्टार्च होता है, चावल में 70 से 80 प्रतिशत, जबकि कसावा में करीब 68 प्रतिशत तक स्टार्च होता है। इसलिए यह प्रोसेसिंग उद्योग के लिए अत्यंत मूल्यवान है। हमने इसकी खेती के लिए मानक कार्यविधियां तैयार कर ली हैं।

संक्षिप्त-समाचार

कनेडा के सांसद टिम सिंह उप्पल सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में हुए नतमस्तक



जैतो। कनेडा के सांसद और विपक्ष के डिप्टी लीडर टिम सिंह उप्पल ने आज अपने परिवार और दोस्तों के साथ सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेककर श्रद्धा व्यक्त की। उनके साथ सरी कुलदीप सिंह प्रभान के.एन.आर. गरुप कनेडा और चरणजीत सिंह मावीकला भी मौजूद थे। इस मौके पर शिरोमणि कमेटी की तरफ से श्री दरबार साहिब के इन्फॉर्मेशन सेंटर में उन्हे शिरोमणि कमेटी सदस्य भाई गुरचरण सिंह गोवाल और इन्फॉर्मेशन ऑफिसर रणधीर सिंह ने सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब का गोल्डन मॉडल और किताबें देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सदस्य भाई गुरचरण सिंह गोवाल ने कहा कि देश और दुनिया में रहने वाले सिखों ने अपनी मेहनत से बहुत बड़ा योगदान दिया है और बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें से एक है टिम सिंह उप्पल, जिन्होंने कनेडा की राजनीति में अपना नाम बनाया है। वे सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में दर्शन के लिए आए थे। टिम सिंह उप्पल और उनके परिवार को बधाई दी। इस मौके पर टिम सिंह उप्पल ने कहा कि सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब देश और दुनिया में रहने वाले सिखों के लिए एक बड़ी आस्था है। यह वह केंद्र है जहां वे सिर झुकते हैं और अपनी खुशकिस्मती महसूस करते हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कमेटी से मिले सम्मान के लिए धन्यवाद किया।

लुधियाना व ढंढारी कलां स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर अस्थायी पाबंदी

जैतो। उत्तर रेलवे के फिरोजपुर रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक परमदीप सिंह सैनी ने सोमवार को कहा कि फिरोजपुर मंडल द्वारा होली के मद्देनजर अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित एवम् रेलवे यात्रियों की सुविधाजनक आगमन को ध्यान में रखते हुए लुधियाना और ढंढारी कलां रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री 27.02.2026 से 03.03.2026 तक अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। फिरोजपुर मंडल रेलयात्रियों से अपील करता है सुखद एवम् आसान देश और दुनिया के लिए आवश्यक जरूरी सामान के साथ सफर करें। ट्रेन में यात्रा करने वाले अपने परिचितों और परिवशकों को रेलवे स्टेशन के बाहर तक ही छोड़े ताकि रेलवे स्टेशन पर अनावश्यक भीड़ ना हो। यात्रियों की सुरक्षा और सुखद यात्रा रेलवे के लिए सर्वोपरि है। सफर के दौरान रेल नियमों का पालन करें, साथ में पटाखे अथवा ज्वलनशील वस्तुएं लेकर यात्रा न करें।

बुलडोजर राजनीति बेनकाब, लोकतंत्र कुचला गया, सत्ता का दुरुपयोग, जनता नहीं भूलेगी: सुखमिंदरपाल

जैतो। राष्ट्रीय भाजपा नेता, एडवोकेट सुखमिंदरपाल सिंह गोवाल भूखंडी कलां ने कहा कि वे अपने मित्र सुखपाल सिंह खेरा के निवास पर की गई शर्मनाक तोड़फोड़ की कार्रवाई की दिल से और पूरी हद तक के साथ बिना करते हैं। उन्होंने कहा कि यह शासन नहीं बल्कि अहंकार और सत्ता के खुले दुरुपयोग से प्रेरित बहकती की राजनीति है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई एक खतरनाक मानसिकता को दर्शाती है जो लोकतंत्र, कानून और मूल मानवीय गरिमा का खुला अपमान करती है। गोवाल ने कहा कि सत्ता अस्थायी होती है लेकिन जनता बदेही स्थायी होती है। उन्होंने कहा कि हर अन्यायपूर्ण कार्रवाई को याद रखा जाएगा, दर्ज किया जाएगा और पंजाब की जनता उसका जाब देगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और अरविंद केजरीवाल जी तथा ऐसे सभी अधिकारियों को, जो आंख बंद कर इस तरह के अन्यायपूर्ण आदेशों को लागू कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि सत्ता का दुरुपयोग ताकत नहीं बल्कि कायरता है, जो सत्ता के पीछे छिपी होती है। उन्होंने कहा कि शासन सेवा के लिए होता है, न कि राजनीतिक बदले के लिए। गोवाल ने आगे कहा कि यह कार्रवाई अत्यंत शर्मनाक, अन्यायपूर्ण और पूरी तरह अस्वीकार्य है।

चितकारा इंटरनेशनल स्कूल में बायोडायवर्सिटी अवेयरनेस सेशन का आयोजन

चंडीगढ़। चितकारा इंटरनेशनल स्कूल में आज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) एक्सपर्ट्स के सहयोग से बायोडायवर्सिटी अवेयरनेस सेशन का आयोजन किया गया। सत्र को 14 वर्षीय युवा एनवायरनमेंटलिस्ट, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर वीर सिंह ने संबोधित किया, जो वीर वनम काउंटेनन से जुड़े हैं। उन्होंने गंभीर रूप से संकटग्रस्त भारतीय सबकॉलिनैट का एक प्रेशर्वेटेड मगरमच्छ- चड़ियाल के संरक्षण पर छात्रों को जागरूक किया। स्टूडेंट्स और फैकल्टी को एड्रेस करते हुए, वीर सिंह ने रिचर इकोसिस्टम की इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर जोर दिया और चड़ियालों को प्रेशर्वेटेड हेल्थ का एक अहम इंडिकेटर बताया। उन्होंने बताया कि कैसे हैबिटेट लॉस, रिचर पॉल्यूशन, गैर-कानूनी रेत माइनिंग और जलवायु परिवर्तन जैसे कारणों से चड़ियालों की संख्या तेजी से कम हो रही है। अपने फील्डवर्क और वाइल्डलाइफ डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर, उन्होंने लगातार कंजर्वेशन की कोशिशें कीं और मजबूत कम्युनिटी अवेयरनेस की जरूरत पर जोर दिया। सेशन में बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन और नेचुरल इकोसिस्टम को बचाने में युवाओं की भूमिका जैसे बड़े टॉपिक भी शामिल थे। स्टूडेंट्स ने देशी प्रजातियों की रक्षा और बचाव, नदियों, वाइल्डलाइफ और इंग्लीश समुदायों के बीच के लिंक को समझने पर चर्चा में एक्टिव रूप से हिस्सा लिया।



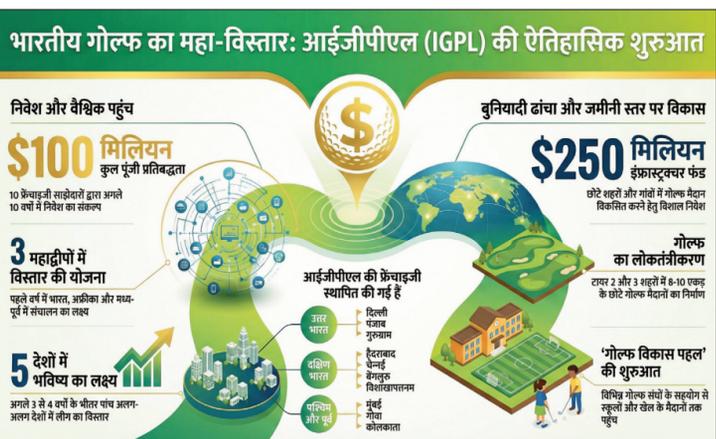
इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग को मिला 100 मिलियन डॉलर का निवेश

10 शहरों में फ्रेंचाइजी घोषित, 250 मिलियन डॉलर का आधारभूत संरचना निवेश

एजेंसी (हि.स.) नई दिल्ली

इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग (आईजीपीएल) ने भारतीय गोल्फ इतिहास के सबसे बड़े निजी निवेश की घोषणा करते हुए 10 फ्रेंचाइजी साझेदारों से 100 मिलियन डॉलर की पूंजी प्रतिबद्धता हासिल की है। प्रत्येक फ्रेंचाइजी ने अगले 10 वर्षों में लगभग 10 मिलियन डॉलर निवेश करने का संकल्प लिया है।

आईजीपीएल ने हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, विशाखापत्तनम, गोवा, बेंगलुरु, पंजाब और गुरुग्राम को अधिकार प्रदान किए हैं। यह प्रारूप देश के प्रमुख महानगरों और उभरते क्षेत्रों तक पेशेवर गोल्फ को पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। लीग संचालन के अलावा साझेदारों ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा



गांवों में 8-10 एकड़ के छोटे गोल्फ मैदान विकसित करने के लिए सामूहिक रूप से 250 मिलियन डॉलर निवेश का लक्ष्य रखा है। इसका उद्देश्य गोल्फ को पारंपरिक अभिजात्य दायरे से बाहर निकालकर आम लोगों तक पहुंचाना है। आईजीपीएल अपने पहले ही वर्ष में भारत, अफ्रीका और मध्य-पूर्व सहित

तीन महाद्वीपों में विस्तार की रणनीति के साथ शुरुआत करेगा। अगले तीन से चार वर्षों में पांच देशों में संचालन का लक्ष्य रखा गया है।

आईजीपीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तम सिंह मुंडी ने कहा कि यह पारंपरिक खेल निवेश नहीं, बल्कि खेल के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का मंच है। उन्होंने कहा कि लीग केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक संपूर्ण गोल्फ तंत्र तैयार कर रही है।

आईजीपीएल ने भारतीय गोल्फ संघ, महिला गोल्फ संघ भारत, पेशेवर गोल्फ संघ भारत और गोल्फ फाउंडेशन के साथ मिलकर हायोगोल्फ विकास पहल शुरू की है। इसके तहत विद्यालयों और खेल मैदानों में गोल्फ को पहुंचाया जाएगा। लीग प्रारूप, प्रतियोगिता कार्यक्रम और खिलाड़ियों की नीलामी से जुड़ी जानकारी जल्द घोषित की जाएगी।

अयोध्या में 'रन फॉर राम 2026' का भव्य समापन



हजारों धावकों ने दिखाई आस्था और फिटनेस की मिसाल

एजेंसी (हि.स.) अयोध्या

धर्मनगरी अयोध्या में रविवार को 'रन फॉर राम' मैराथन 2026 का चौथा संस्करण भव्य रूप से संपन्न हुआ। राम कथा पार्क में आयोजित इस आयोजन में देश-विदेश से हजारों प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह मैराथन क्रीड़ा भारतीय द्वारा आयोजित की गई, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में कायंरत है। मैराथन की शुरुआत लता मंगेशकर चौक से हुई और इसका समापन राम कथा पार्क में हुआ। आयोजन की थीम प्राचीन 14-कोसी परिक्रमा से प्रेरित रही, जो धैर्य, अनुशासन और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। इस वर्ष महिला प्रतिभागियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसमें 100 से अधिक महिला धावकों ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

क्रीड़ा भारती उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अवनीश कुमार सिंह ने कहा कि चौथे संस्करण की सफलता अत्यंत गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि सभी आयु वर्ग के लोगों की भागीदारी अयोध्या की ऊर्जा, अनुशासन और

टी20 विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने बुमराह, अश्विन का रिकॉर्ड तोड़ा



नई दिल्ली। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने सुपर-8 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। बुमराह ने इस मैच से पहले पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के 32 विकेट के रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए तीन विकेट की जरूरत थी। उन्होंने चार ओवर में मात्र 15 रन देकर तीन महत्वपूर्ण विकेट झटकें और अश्विन को पीछे छोड़ दिया। बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज विंस्टन डी कोक, रयान रिक्केटन और कॉर्बिन बोश को पवेलियन भेजकर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। इस प्रदर्शन के साथ बुमराह के टी20 वर्ल्ड कप में कुल 33 विकेट हो गए हैं। हालांकि मैच में भारत को 76 रनों की करारी हार का सामना करना पड़ा, जिससे उनके इस प्रदर्शन की चमक थोड़ी धीमी पड़ गई।

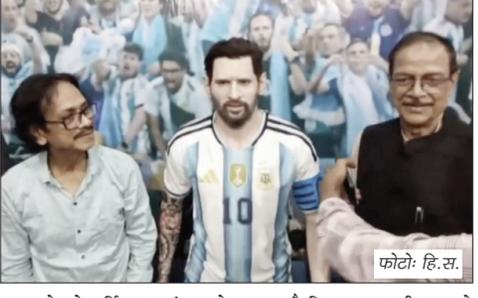
टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट

- जसप्रीत बुमराह - 33 विकेट (22 पारियां)
- अश्विन सिंह - 32 विकेट (18 पारियां)
- रविचंद्रन अश्विन - 32 विकेट (24 पारियां)
- हादिक पांड्या - 29 विकेट (26 पारियां)
- रवींद्र जडेजा - 22 विकेट (29 पारियां)

अक्षर को बाहर रखने के फैसले को टेन डेडोशे ने रणनीतिक बताया

अहमदाबाद। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 विश्व कप के सुपर आठ मुकाबले में उपकप्तान अक्षर पटेल को बाहर रखने के फैसले की काफी आलोचना हो रही है लेकिन भारतीय टीम के सहायक कोच रियान टेन डेडोशे और बल्लेबाजी कोच सितार्थो कोटक ने कहा कि यह फैसला पूरी तरह से रणनीतिक कारणों से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 76 रन से हराया और चौथिंगटन सुंदर बल्ले तथा गेंद दोनों से फ्लॉप रहे जिन्हें अक्षर की जगह उतारा गया था। टेन डेडोशे ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने पिछले कुछ दिनों में अंतिम एकादश पर काफी मंथन किया। हम मैच अप पर विचार कर रहे थे। वैसे अक्षर को उतारने का फैसला सही लग रहा था लेकिन हमें आठवें बल्लेबाज के रूप में अक्षर की जरूरत थी। यह फैसला उसी आधार पर लिया गया। उन्होंने कहा, अक्षर की नेतृत्व क्षमता और अहमियत हम सभी जानते हैं।

आसनसोल में लियोनेल मेसी की प्रतिमा का अनावरण



एजेंसी (हि.स.) आसनसोल

राज्य के श्रम विधि व न्याय मंत्री मलय घटक ने रविवार की संस्था आसनसोल में भी अर्जेंटीना के विख्यात फुटबॉलर लियोनेल मेसी की प्रतिमा का अनावरण किया। आसनसोल के मोहिशीला इलाके के निवासी और मूर्तिकार सुशांत राय ने मेसी की जीवंत मॉम की प्रतिमा तैयार कर शहरवासियों को एक अनोखा तोहफा दिया है।

गौरतलब है कि 13 दिसंबर 2025 को कोलकाता के लोक टाउन स्थित श्रीभूमि स्पोर्ट्स क्लब द्वारा निर्मित 70 फुट ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। यह प्रतिमा मेसी को कतर 2022 विश्व कप जीत का जश्न मनाते हुए दर्शाती है। मेसी ने अपने गो एट इंडिया टूर 2025 के दौरान वर्चुअल माध्यम से इस प्रतिमा का उद्घाटन किया था। इस भव्य प्रतिमा को भारत में फुटबॉल के प्रति जुनून और मेसी के प्रति प्रशंसकों के प्यार का प्रतीक माना गया। इसी कड़ी में

प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश के आरोप से लियोनेल मेसी को मिली वलीन चिट



एजेंसी (हि.स.) नई दिल्ली

मेजर लीग सॉकर (एमएलएस) ने समीक्षा के बाद स्पष्ट किया है कि स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया। इंटर मियामी की सत्र की शुरुआत में मिली 0-3 की हार के बाद मैच अधिकारियों के पीछे एक दरवाजे से अंदर जाने को लेकर उन पर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने का आरोप लगा था। यह घटना शनिवार को एमएलएस के मुकाबले के दौरान हुई, जब इंटर मियामी सीएफ को लॉस एंजिल्स एफसी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।

लीग प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि वीडियो फुटेज की समीक्षा के बाद यह पाया गया कि मेसी जिस स्थान पर गए थे, वह न तो रेफरी की ड्रैसिंग रूम था और न ही कोई प्रतिबंधित क्षेत्र। इसलिए किसी भी नैतिक उल्लंघन नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में इंटर मियामी के

खाना-खजाना दर्पण

बाजार जैसा टेस्टी कांजी वड़ा घर पर बनाने का आसान तरीका



होली का त्योहार आते ही घरों में गुजिया, दही बड़े और ठंडाई की तैयारी शुरू हो जाती है। इसी के साथ एक और खास डिश है जो खासतौर पर उत्तर भारत में बहुत पसंद की जाती है, कांजी वड़ा। खट्टा-तीखा, हल्का मसालेदार और प्रोबायोटिक गुणों से भरपूर कांजी वड़ा होली की थाली को खास बना देता है। अच्छी बात यह है कि इसे दो-तीन दिन पहले से तैयार करना पड़ता है, ताकि इसका स्वाद पूरी तरह निखर आए। अगर आप चाहते हैं कि इस होली मेहमान आपके खाने की तारीफ करते न थकें, तो कांजी वड़ा जरूर बनाएं। बस याद रखें कि इसे दो-तीन दिन पहले तैयार करना है। इस बार होली में अपने मेहमानों को कुछ अलग परोसने के लिए ये सैक्स परफेक्ट है, जिसे बनाना भी आसान है। अभी से कांजी वड़ा की रेसिपी सेव करके रख लें।

कांजी वड़ा क्या है

कांजी वड़ा एक पारंपरिक उत्तर भारतीय डिश है जिसमें उड़द दाल के वड़े खट्टी-तीखी राई वाली फर्मेंटेड पानी (कांजी) में डाले जाते हैं। 12-3 दिन की धूप में रखने के बाद इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।

कांजी वड़ा के फायदे

पाचन के लिए फायदेमंद, प्राकृतिक प्रोबायोटिक, हल्का और हेल्दी, त्योहार के भारी खाने के बीच संतुलन बनाए

होली पर कांजी वड़ा क्यों खास है

होली का त्योहार रंगों के साथ स्वाद का भी उत्सव है। जैसे होली पर गुजिया और ठंडाई का महत्व है, वैसे ही कांजी वड़ा भी कई घरों की पारंपरिक पहचान है। यह डिश त्योहार के भारी और मीठे पकवानों के बीच एक हल्का, खट्टा और ताजगीभरा विकल्प देती है।

पुआ हो जाते हैं पत्थर जैसे टाइट तो नोट करें ये रेसिपी, बनेंगे एकदम सॉफ्ट-सॉफ्ट



होली का त्योहार सिर्फ रंगों का ही नहीं, बल्कि इस त्योहार में स्वादिष्ट पकवानों की भी खास जगह होती है। इस खास मौके पर घर-घर में गुजिया, दही भल्ले और मालपुआ के साथ पारंपरिक पुआ जरूर बनाया जाता है। उत्तर भारत के कई राज्यों में होली के दिन पुआ बनाना शुभ माना जाता है। दादी-नानी के समय से चली आ रही इस रेसिपी में न तो ज्यादा सामग्री लगती है और न ही ज्यादा समय, लेकिन स्वाद ऐसा कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाए। खास बात यह है कि यह रेसिपी पूरी तरह देसी अंदाज में बनती है, जिसमें सौंफ, इलायची और गुड़ या चीनी की मिठास का बेहतरीन मेल होता है। अगर आप भी इस होली पर पारंपरिक स्वाद का आनंद लेना चाहते हैं, तो इस आसान और क्लासिक पुआ रेसिपी को जरूर ट्राई करें।

पुआ बनाने की सामग्री

- 1 कप गेहूं का आटा
- 1/2 कप सूजी (ऑफ़नल, कुरकुरापन के लिए)
- 3/4 कप गुड़ (या एकप चूनी)
- 1 कप दूध
- 2-3 छोटी इलायची पाउडर
- 1 छोटा चम्मच सौंफ
- 1-2 चम्मच कसा हुआ नारियल (ऑफ़नल)
- घी या तेल तलने के लिए

स्टेप 1

- उड़द दाल को 5-6 घंटे भिगो दें।
- पानी निकालकर बारीक पीस लें।
- मिश्रण को 5-7 मिनट अच्छी तरह फेंटें ताकि वड़े मुलायम बनें।
- गरम तेल में छोटे-छोटे वड़े तल लें।
- तले हुए वड़ों को गुनगुने पानी में 10 मिनट डालें, फिर हल्का नियोके लें।

स्टेप 2

- तैयार वड़ों को कांजी में डाल दें।
- एक दिन के लिए फिर से ढककर रख दें।
- अब आपका स्वादिष्ट कांजी वड़ा सर्व करने के लिए तैयार है।

बनाने के टिप्स

- हमेशा साफ और सूखा बर्तन इस्तेमाल करें।
- अगर मौसम ठंडा है, तो 3-4 दिन लग सकते हैं।
- धूप अच्छी मिले तो स्वाद बेहतर आता है।
- ज्यादा खट्टा पसंद हो तो दिन और फर्मेंट होने दें।

सांगम

- चावल - 1 कटोरी
- पानी - 2 कटोरी
- स्वादानुसार नमक
- तलने के लिए तेल
- काली मिर्च - 1/2 छोटा चम्मच
- घी - 1 बड़ा चम्मच

चावल की कचरी बनाने का सबसे सरल तरीका

होली का त्योहार रंगों, खुशियों और स्वादिष्ट पकवानों का प्रतीक है। इस समय घरों में खासतौर पर पापड़, गुजिया और अन्य मिठाइयां बनती हैं। अगर आप कुछ अलग और टेस्टी बनाने का मन बना रही हैं, तो चावल की कचरी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। ये न केवल स्वाद में लाजवाब होती है, बल्कि इसे घर में आसानी से तैयार भी किया जा सकता है। खास बात यह है कि अगर इसे सही तरीके से बनाया जाए, तो यह सालभर ताजगी से बनी रहती है। चावल की कचरी

चावल की कचरी बनाने के लिए सबसे पहले 1 कटोरी चावल को अच्छे से धोकर 2 कटोरी पानी में डालकर कुकर में डालें। फिर उसमें स्वादानुसार नमक, काली मिर्च पाउडर और 1 बड़ा चम्मच घी डालें। इन सब चीजों को अच्छे से मिला लें और कुकर का ढक्कन बंद करके 3-4 सीटी आने तक उबालने के लिए रख दें। अब चावल को हल्का गीला रखें ताकि कचरी नरम बने और पकने के बाद आसानी से मेश किया जा सके। जब कुकर का प्रेशर निकल जाए, तब ढक्कन खोलकर चावल को अच्छे से मेश कर लें। मेश किए हुए चावल को अब पाइपिंग बेग में डालें, ताकि आप इसे ठीक से शेप दे सकें। इसके लिए एक साफ पॉलीथीन बिछा लें और पाइपिंग बेग की मदद से पॉलीथीन पर लम्बी-लम्बी या गोल आकार की कचरी बना लें। आप इन्हें अपनी पसंद के आकार में बना सकती हैं। अब इन कचरी को 1-2 दिन तक धूप में सुखा लें, ताकि ये पूरी तरह से सूख जाएं। जब कचरी पूरी तरह से सूख जाए, तो इन्हें तला जा सकता है। एक कढ़ाई में तेल गरम करें और कचरी को सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलें। तलने के बाद, कचरी को फिचन टॉवल पर रखें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए। ये कचरी चाय, दही या अपनी पसंदीदा चटनी के साथ सर्व की जा सकती है। ये कुरकुरी, स्वादिष्ट और ताजगी से भरपूर होती है। आप इसे सालभर तक सुरक्षित रख सकती हैं, क्योंकि यह लंबे समय तक ताजगी बनी रहती है। होली जैसे त्योहारों पर यह एक बेहतरीन स्नेक बन सकती है, और घर के सभी सदस्य इसे चाव से खाएंगे।

हरियाणा के युवा हर क्षेत्र में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं: भारत भूषण भारती

भारत भूषण भारती ने 153 किलोमीटर ट्रेकिंग पूरी करने वाले विद्यार्थियों को दी बधाई, युवाओं की क्षमता को सराहा

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय (एमडीयू) के विद्यार्थियों ने नेचर कैम्प थपली में आयोजित दो दिवसीय ट्रेकिंग एवं शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह विशेष भ्रमण हरियाणा सरकार के युवा कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया।



और उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार के साहसिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रम युवाओं में नेतृत्व क्षमता, टीम भावना तथा आत्मविश्वास को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत भूषण भारती ने विद्यार्थियों को जीवन में अनुशासन, लक्ष्य निर्धारण और सकारात्मक सोच अपनाने का संदेश देते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं को

खेल, शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वे प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। युवा कल्याण संयोजक नरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दो दिवसीय विशेष यात्रा को उद्देश्य विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रकृति के निकट लाना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना तथा जलवायु परिवर्तन

जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर ज्ञानवर्धन करना है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पहचान रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी रेंजर विजय नेहरा ने विद्यार्थियों को जलवायु परिवर्तन विषय पर विस्तृत व्याख्यान दिया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के

कारणों, इसके दुष्परभावों तथा इससे निपटने के उपायों पर प्रकाश डाला। विद्यार्थियों ने व्याख्यान में गहरी रुचि दिखाई और विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से विषय को गहन जानकारी प्राप्त की। विद्यार्थियों ने ट्रेकिंग के साथ-साथ प्राकृतिक वातावरण का अवलोकन किया तथा जैव विविधता के संरक्षण के महत्व को समझा। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना और उन्हें सतत विकास के लिए प्रेरित करना रहा।

चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय (सीबीएलयू), भिवानी के विद्यार्थी नेचर कैम्प थपली का अवलोकन करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थी ट्रेकिंग गतिविधियों में भाग लेंगे। विद्यार्थी प्राकृतिक परिवेश में रहकर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे तथा प्रकृति के विविध आयामों को निकट से समझेंगे।

होमी भाभा कैंसर अस्पताल में खेलों के जरिए बढ़ा तालमेल

सिटी दर्पण संवाददाता
न्यू चंडीगढ़

होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र पंजाब द्वारा आयोजित सालाना खेल महोत्सव 'मेटाप्लेजिया 2026' का रिविवा को बड़े उत्साह के साथ समापन हुआ। 16 फरवरी से शुरू हुए सप्ताह भर के आयोजन में न्यू चंडीगढ़ और संगरूर, दोनों यूनिट्स के फेकल्टी मेंबर्स, रोजिडेंट डॉक्टर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स और बाकी स्टाफ ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

इस समापन समारोह में चंडीगढ़ टचवर्कर की डायरेक्टर डॉ. ज्योत्सना सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। साथ ही, उत्साह फाउंडेशन के उपाध्यक्ष श्री संजीव शर्मा भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे।

अस्पताल के डायरेक्टर डॉ. आशीष गुलिया ने इस मौके पर कहा कि खेलों का महकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि संस्थान में एकता बढ़ाना है। उन्होंने कहा, खेल भावना और टीम वर्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।



जिस तरह मरीजों के इलाज में तालमेल और भरोसे की जरूरत होती है, वैसे ही खेल भी हमें साथ मिलकर काम करना सिखाते हैं।

मुख्य अतिथि डॉ. ज्योत्सना सिंह ने अस्पताल की तारीफ करते हुए कहा कि पढ़ाई और काम के साथ-साथ सेहत और खेलों को बढ़ावा देना काबिल-ए-तारीफ है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से प्रोफेशनल्स न केवल कुशल बनते हैं, बल्कि वे अनुशासन और टीम के साथ चलना भी सीखते हैं। 'मेटाप्लेजिया 2026' में शतरंज, कैरम, पुश-अप और बैच प्रेस जैसे इंडोर गेम्स से लेकर रेस (100 मीटर से 1000 मीटर), स्लो साइकिलिंग, स्नून

रेस, बैडमिंटन, फुटबॉल और क्रिकेट जैसे कई मुकाबले हुए। आपको बता दें कि पंजाब और आसपास के राज्यों को बेहतरीन कैंसर इलाज देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2022 में इस अस्पताल को राष्ट्र को समर्पित किया था। टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा 660 करोड़ की लागत से बना यह 300 बेड वाला अस्पताल हर आधुनिक सुविधा (जैसे सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और बोनोमो ट्रांसप्लांट) से लैस है। यह अस्पताल एक मुख्य केंद्र की तरह काम करता है, जबकि संगरूर वाला 150 बेड का अस्पताल इसकी एक शाखा के रूप में मरीजों की सेवा कर रहा है।

एसडी कॉलेज में एआर-वीआर पर टेक्निकल लेकर आयोजित

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

सेक्टर-32 स्थित गोस्वामी गणेश दत्त स्नातन धर्म कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस विभाग की ओर से पीएम-उषा योजना के तहत ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर) और वर्चुअल रियलिटी (वीआर) पर एक टेक्निकल लेकर का आयोजन किया। इस लेकर का उद्देश्य विद्यार्थियों को उभरती हुई इमर्सिव तकनीकों से परिचित कराना तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और अनुसंधान के क्षेत्र में उनके वास्तविक जीवन में उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान करना था। इस सत्र के रिसोर्स पर्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एनआईईएलआईटी) के डिप्टी डायरेक्टर (सिस्टम्स) डॉ. सरवण सिंह थे, जिन्होंने एक ज्ञानवर्धक एवं तकनीकी रूप से समृद्ध लेकर प्रस्तुत किया। उन्होंने एआर और वीआर के मूल सिद्धांतों, नई



तकनीकी प्रगतियों और दवा, रक्षा तथा खेल जैसे क्षेत्रों में इनके उपयोग के बारे में समझ तारीके से जानकारी दी। साथ ही, इस क्षेत्र में भविष्य के रुझानों और करियर के अवसरों पर भी विस्तार से बताया। सत्र काफ़ी रोचक और इंटरैक्टिव रहा, जिसमें छात्रों ने सवाल पूछकर और चर्चा में भाग लेकर सक्रिय सहभागिता दिखाई। यह इवेंट कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. अजय शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। उन्होंने इस तरह के तकनीकी से जुड़े शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विभाग की सराहना की और कहा कि नई तकनीकों की जानकारी छात्रों को

भविष्य के लिए तैयार करने में मदद करती है। विभागाध्यक्ष डॉ. रीना ने आधुनिक कंप्यूटिंग शिक्षा में एआर और वीआर की उपयोगिता पर प्रकाश डाला और छात्रों को इस क्षेत्र में शोध एवं नवाचार के लिए प्रेरित किया। लेकर का सफल समन्वय डॉ. शैलजा अग्निहोत्री और ओजस्वी आनंद द्वारा किया गया, जिससे कार्यक्रम का संचालन सुचारु रूप से सुनिश्चित हुआ। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसमें संस्थापक वर्यिक एवं सभी गणमान्य अतिथियों की गरिमान्वयी उपस्थिति और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया गया। यह कार्यक्रम पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी और ज्ञानवर्धक साबित हुआ। यह उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शैक्षणिक एवं कौशल आधारित पहलों को बढ़ावा देने वाली पीएम-उषा योजना के लक्ष्यों के अनुरूप रहा।

एनएचपीसी द्वारा वसंत उत्सव 2026 का आयोजन

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

वसंत उत्सव के दौरान श्री भूपेन्द्र गुप्ता, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी, श्रीमती शिखा गुप्ता, अध्यक्ष, एनएचपीसी महिला कल्याण समिति। इस अवसर पर श्री उत्तम लाल, निदेशक (कार्मिक), श्री संजय कुमार सिंह, निदेशक (परियोजनाएं), श्री सुप्रकाश अधिकारी, निदेशक (तकनीकी) तथा एनएचपीसी महिला कल्याण समिति की सदस्याएं श्रीमती मोना लाल, श्रीमती गरिमा सिंह तथा श्रीमती सोमा अधिकारी भी उपस्थित थीं।

एनएचपीसी, भारत की 100 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी द्वारा दिनांक 22.02.2026 को एनएचपीसी आवासिय परिसर, फरीदाबाद में ह्रावसंत उत्सव 2026कबड़े धूम-धाम से मनाया गया। उत्सव का उद्घाटन श्री भूपेन्द्र गुप्ता, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी तथा श्रीमती शिखा गुप्ता, अध्यक्ष,



एनएचपीसी महिला कल्याण समिति द्वारा किया गया। एनएचपीसी द्वारा वसंत ऋतु के दौरान भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से वसंत उत्सव मनाया जाता है।

कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक महोदय ने उपस्थित जनों को शुभकामनाएं दी तथा और कहा कि वसंत ऋतु हमारे जीवन में नई ऊर्जा, नई उमंग और नई आशा का संचार करती है। सदियों की टिड्डुरन के पश्चात जब मौसम सुहावना हो जाता है,

खेतों में फसलें लहलहाते लगती हैं, वृक्षों पर नई कोपलें फूटती हैं और चारों ओर रंग-बिरंगी फूल खिल उठते हैं, तब प्रकृति हमें बड़ा संदेश देती है कि परिवर्तन ही जीवन का आधार है और प्रत्येक उदाराव के बाद आगे बढ़ना ही प्रगति का मार्ग है। अपने सम्बन्धन में श्री गुप्ता ने एनएचपीसी की निमाणाधीन परियोजनाओं तथा भविष्य की स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु एनएचपीसी पावर स्टेशनों/परि योजनाएं/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्टाल भी लगाए गए थे।

को पूरा किया है, बल्कि कई मामलों में उससे आगे बढ़कर उत्कृष्ट प्रदर्शन भी किया है।

इस अवसर पर श्री उत्तम लाल, निदेशक (कार्मिक), श्री संजय कुमार सिंह, निदेशक (परियोजनाएं), श्री सुप्रकाश अधिकारी, निदेशक (तकनीकी) तथा एनएचपीसी महिला कल्याण समिति की सदस्याएं श्रीमती मोना लाल, श्रीमती गरिमा सिंह तथा श्रीमती सोमा अधिकारी भी उपस्थित थीं। इस उत्सव में मधुरा के स्थानीय कलाकारों द्वारा लोकगीत-संगीत तथा लोक नृत्य का प्रदर्शन किया गया जिनकी शानदार प्रस्तुतियों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस उत्सव में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम आदि विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु एनएचपीसी पावर स्टेशनों/परि योजनाएं/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्टाल भी लगाए गए थे।

चंडीगढ़ में स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल का गठन, डॉ. अजय शर्मा और प्रो. रजत संधीर बने सदस्य

चंडीगढ़। केंद्र सरकार की रूसा/पीएम-उषा योजना के तहत चंडीगढ़ में उच्च शिक्षा के समग्र विकास के उद्देश्य से स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल का गठन किया गया है। काउंसिल यूटी के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में कार्य करेगी और शहर में उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल, संसाधनों के साझा उपयोग तथा शैक्षणिक सुधारों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। काउंसिल में यूटी प्रशासक के मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद को वाइस-चेयरमैन तथा यूटी प्रशासन की शिक्षा सचिव प्रेरणा पुरी को सदस्य सचिव बनाया गया है, जबकि उच्च शिक्षा निदेशक, चंडीगढ़ प्रशासन स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में शामिल हैं। काउंसिल में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ यूनिवर्सिटीज, कॉलेजों, इंटरमीडिएट, संस्कृति, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। काउंसिल में पंजाब यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, यूआईईटी पंजाब यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी, मोहाली तथा चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया गया है। काउंसिल में स्टेट यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर के रूप में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की वीसी प्रो. रेनु विग, एनपीयू जालंधर के वीसी प्रो. जसपाल सिंह संघु तथा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर के वीसी प्रो. कर्मजीत सिंह को शामिल किया गया है। वहीं, एफिलेटेड कॉलेजों का प्रतिनिधित्व जीजीडीएसडी कॉलेज, सेक्टर-32 के प्रिंसिपल डॉ. अजय शर्मा तथा गर्नमैट कॉलेज ऑफ इंजुकेशन, सेक्टर-20 की प्रिंसिपल डॉ. सपना नंदा करेंगे। आर्ट्स एंड कामर्स क्षेत्र से उच्च शिक्षा विभाग के राज्य नोडल अधिकारी (एनईपी 2020) एवं राज्य नोडल अधिकारी (एआईएसएवई) को काउंसिल में स्थान दिया गया है। साइंस क्षेत्र में पंजाब यूनिवर्सिटी के रूसा कोऑर्डिनेटर प्रो. गंगा राम चौधरी तथा प्रो. रजत संधीर सदस्य बनाए गए हैं। टेक्नोलॉजी क्षेत्र से पेक के प्रो. संजय बालिश, यूआईईटी के प्रो. नवीन अग्रवाल तथा डॉ. धीरेंद्र तापल को शामिल किया गया है। संस्कृति क्षेत्र में पूर्व आईएस कांशिश मिताल एवं डॉ. कुलदीप चंद अग्निहोत्री को स्थान दिया गया है, जबकि शिक्षित सोसायटी का प्रतिनिधित्व जनरल (सेवानिवृत्त) केज. सिंह, उरबी गुलाटी (पूर्व आईएस) तथा समाजसेवी जगमोहन गंज कर रहे हैं।



जाएगी। बंभर भारत में डिजाइन एवं निर्मित हैं। इंटू-सिटी (शहरी) सार्वजनिक परिवहन के लिए कॉर्नर गर की गई। उन्होंने बताया कि चार्जिंग एवं अवसंरचना - डिपो आधारित उउर फास्ट चार्जिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। रात्रिकालीन निर्धारित चार्जिंग व्यवस्था, लगभग 2इ3 घंटे में पूर्ण चार्ज (बैटरी स्थिति पर निर्भर), स्मार्ट लोड मैनेजमेंट प्रणाली से बिजली मांग के अनुकूलन के अलावा, अर्थिंग, अग्नि सुरक्षा एवं विद्युत सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया गया है। स्थानीय प्राधिकरणों के साथ समन्वित विद्युत लोड योजना के अलावा सुरक्षा एवं यात्री सुविधाएं लो-फ्लोर प्रवेश व सुगम चढ़ने-उतरने की सुविधा एवम् सीसीटीवी कैमरा एवं आंतरिक निगरानी प्रणाली से लैस है। उन्होंने बताया कि यात्री सुचना डिस्प्ले सिस्टम, आपातकालीन स्टॉप व सुरक्षा अनुपालन सुविधाएं, रखरखाव एवं सेवा समर्थन उच्च परिचालन उपलब्धता लक्ष्य, रिमोट डायग्नोस्टिक्स

आधारित प्रिवेंटिव व प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, बैटरी स्वास्थ्य निगरानी व थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम, डिपो पर सर्मापित सेवा इंजीनियर व तकनीकी दल, सेयर पार्ट्स स्पॉट व त्वरित सेवा प्रोटोकॉल के अलावा अन्य यह अत्य आधुनिक सेवाओं से लैस है। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने इटैलीजैट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। इस कंट्रोल रूम से सिटी बस सेवा की विभिन्न गतिविधियों की आनलाईन निगरानी सिस्टम का अवलोकन किया एवम जानकारी ली। यह बसें वातावरण अनुकूल है जो प्रदूषण नहीं करती हैं। जिस से शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण में कमी के अलावा स्वच्छ, हरित एवं टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। चंडीगढ़ प्रेस वीर के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब का दौरा किया। इस दौरान विभिन्न मीडिया संस्थानों के पत्रकारों से विचार-विमर्श किया।

प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ (यूटी) के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया से शिष्टाचार भेंट की

राजस्थान के पत्रकार प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़, पंजाब-हरियाणा में केंद्र की संचालित योजनों की प्रगति का क्रिया अवलोकन

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), जयपुर द्वारा राजस्थान राज्य के वरिष्ठ संपादकों एवं रिपोर्टरों के पत्रकार दल ने इस दौरे के दौरान पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ (यूटी) के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रेस दौरे के उद्देश्य के बारे में विस्तार से चर्चा की गई।

प्रेस दौरे के अंतिम दिन दल ने चंडीगढ़ परिवहन विभाग में डटी-इ२२ रीढ़ योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर परिवहन विभाग के चीफ ऑपरेशनल मैनेजर श्री यशजीत गुप्ता ने बताया कि भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा चंडीगढ़ शहर के लिए कुल 428 बसों को स्वीकृति प्रदान की गई। वर्तमान में शहर में 80 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही थीं। 25 नई बसों के शामिल होने से यह संख्या बढ़कर 105 हो गई है। उन्होंने बताया कि नई शामिल की



गई 12 मीटर लंबी लो-फ्लोर, वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें एक बार चार्ज होने पर लगभग 224 किलोमीटर तक चलने में सक्षम हैं। इनमें 400 मिमी लो-फ्लोर सुविधा, दिव्यांगजन यात्रियों के लिए पावर ऑपरेटेड रैंप एवं अन्य अत्य आधुनिक सुविधा, 36 यात्रियों के बैठने तथा 20 यात्रियों के खड़े होने की क्षमता, व्हीलचेयर के लिए विशेष स्थान, एयर सर्किलेशन, फ्रंट डिस्क ब्रेक, यात्री सूचना डिस्प्ले तथा वॉयस-आधारित अगला स्टॉप घोषणा प्रणाली जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

इलेक्ट्रिक बसों से प्रतिस्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त 70 और बसें बेड़े में शामिल की जाएंगी। इस प्रकार कुल इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 508 तक पहुंच जाएगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी, शहरी परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा। चंडीगढ़ सिटी बस सर्विसेज सोसाइटी चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के अंतर्गत, भारत सरकार की पीएम ई-बस सेवा (डटी-इ२२ रीढ़) पहल के तहत इलेक्ट्रिक बसों का संचालन कर रही है। इन बसों का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 फरवरी, 2026 को किया गया, जिसके साथ शहर में पहले चरण की इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत हुई। श्री गुप्ता ने बताया कि प्लॉट अवलोकन के अंतर्गत वर्तमान में 25 इलेक्ट्रिक बसें चंडीगढ़ में शामिल की गई हैं। शेष 100 बसें वर्ष 2026 के दौरान चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई

जाएगी। बंभर भारत में डिजाइन एवं निर्मित हैं। इंटू-सिटी (शहरी) सार्वजनिक परिवहन के लिए कॉर्नर गर की गई। उन्होंने बताया कि चार्जिंग एवं अवसंरचना - डिपो आधारित उउर फास्ट चार्जिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। रात्रिकालीन निर्धारित चार्जिंग व्यवस्था, लगभग 2इ3 घंटे में पूर्ण चार्ज (बैटरी स्थिति पर निर्भर), स्मार्ट लोड मैनेजमेंट प्रणाली से बिजली मांग के अनुकूलन के अलावा, अर्थिंग, अग्नि सुरक्षा एवं विद्युत सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया गया है। स्थानीय प्राधिकरणों के साथ समन्वित विद्युत लोड योजना के अलावा सुरक्षा एवं यात्री सुविधाएं लो-फ्लोर प्रवेश व सुगम चढ़ने-उतरने की सुविधा एवम् सीसीटीवी कैमरा एवं आंतरिक निगरानी प्रणाली से लैस है। उन्होंने बताया कि यात्री सुचना डिस्प्ले सिस्टम, आपातकालीन स्टॉप व सुरक्षा अनुपालन सुविधाएं, रखरखाव एवं सेवा समर्थन उच्च परिचालन उपलब्धता लक्ष्य, रिमोट डायग्नोस्टिक्स

आधारित प्रिवेंटिव व प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, बैटरी स्वास्थ्य निगरानी व थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम, डिपो पर सर्मापित सेवा इंजीनियर व तकनीकी दल, सेयर पार्ट्स स्पॉट व त्वरित सेवा प्रोटोकॉल के अलावा अन्य यह अत्य आधुनिक सेवाओं से लैस है। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने इटैलीजैट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। इस कंट्रोल रूम से सिटी बस सेवा की विभिन्न गतिविधियों की आनलाईन निगरानी सिस्टम का अवलोकन किया एवम जानकारी ली। यह बसें वातावरण अनुकूल है जो प्रदूषण नहीं करती हैं। जिस से शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण में कमी के अलावा स्वच्छ, हरित एवं टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। चंडीगढ़ प्रेस वीर के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब का दौरा किया। इस दौरान विभिन्न मीडिया संस्थानों के पत्रकारों से विचार-विमर्श किया।

आधारित प्रिवेंटिव व प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, बैटरी स्वास्थ्य निगरानी व थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम, डिपो पर सर्मापित सेवा इंजीनियर व तकनीकी दल, सेयर पार्ट्स स्पॉट व त्वरित सेवा प्रोटोकॉल के अलावा अन्य यह अत्य आधुनिक सेवाओं से लैस है। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने इटैलीजैट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। इस कंट्रोल रूम से सिटी बस सेवा की विभिन्न गतिविधियों की आनलाईन निगरानी सिस्टम का अवलोकन किया एवम जानकारी ली। यह बसें वातावरण अनुकूल है जो प्रदूषण नहीं करती हैं। जिस से शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण में कमी के अलावा स्वच्छ, हरित एवं टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। चंडीगढ़ प्रेस वीर के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब का दौरा किया। इस दौरान विभिन्न मीडिया संस्थानों के पत्रकारों से विचार-विमर्श किया।



- एसडीएम पंचकूला को अमरपुर के लोगों के वोट कटने को लेकर जांच के लिए निर्देश
- डीसी ने जिलावासियों से समाधान शिविर में आकर अपनी समस्याओं का जल्द समाधान करवाने की करी अपील

सुविधाओं व योजनाओं का लाभ मिल सके व उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नाथ सिंह सैनी की मंशा है कि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग कार्यालयों में न जाना पड़े। इसी सोच के अनुरूप मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हर कार्यदिवस के दिन लघु सचिवालय के सभागार में सोमवार व वीरवार को प्रात 10 बजे से 12 बजे तक समाधान शिविर का आयोजन किया जाता है जहां सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहते हैं। मुख्यमंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी समस्याओं पर की गई कारवाई का फीडबैक लेते हैं। इस अवसर पर नगरपालिका जयपुरि, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी विशाल पराशर, जिला बागवानी अधिकारी अशोक कौशिक, तहसीदार सुरेश, सहायक मूक संरक्षण अधिकारी राहुल ब्रककोदिया, सीएम विंडो के एफ़मेंट पर्सन सत्यवान भारद्वाज, विपिन लिडडू सहित जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, एचएसवीपी, पीएमडीए, पुलिस, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

से बातचीत करते हैं और उनकी समस्याओं पर की गई कारवाई का फीडबैक लेते हैं। इस अवसर पर नगरपालिका जयपुरि, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी विशाल पराशर, जिला बागवानी अधिकारी अशोक कौशिक, तहसीदार सुरेश, सहायक मूक संरक्षण अधिकारी राहुल ब्रककोदिया, सीएम विंडो के एफ़मेंट पर्सन सत्यवान भारद्वाज, विपिन लिडडू सहित जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, एचएसवीपी, पीएमडीए, पुलिस, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

संक्षिप्त-समाचार

रेखा शर्मा ने पंचकूला में की जनसुनवाई



पंचकूला। श्रीमती रेखा शर्मा, राज्यसभा सांसद, ने पंचकूला लघु सचिवालय में स्थित अपने कार्यालय में जनसुनवाई की। इस दौरान विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि, गांवों के सरपंच, स्थानीय जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के नागरिक उनसे मिलने पहुंचे। जनसुनवाई में पंचायत विभाग, लोक निर्माण विभाग (ढहउ), पुलिस और होमगार्ड विभाग से जुड़ी समस्याओं और शिकायतों को विस्तार से सुना गया। श्रीमती रेखा शर्मा ने सभी की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और भरोसा दिलाया कि संबंधित विभागों के अधिकारियों से बात कर समस्याओं का जल्द और प्रभावी समाधान कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और हर नागरिक की समस्या का समाधान करना उनकी प्रतिबद्धता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनसहभागिता और निरंतर संवाद के माध्यम से क्षेत्र के विकास को और गति मिलेगी।

एसडीएम (पूर्व) द्वारा शिक्षा विशेष निस्तारण न्यायालय आयोजित

चंडीगढ़। समग्रबद्ध न्याय सुनिश्चित करने तथा उत्तरदायी प्रशासन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक विशेष पहल के तहत उप-मंडल दंडाधिकारी (पूर्व), चंडीगढ़ द्वारा कल एक विशेष निस्तारण न्यायालय का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अंतिम निर्णय हेतु परिपक्व मामलों का बड़े स्तर पर निपटारा किया जाएगा। सुनिश्चित सभी एक मामलों के पृथक्करण के उपरांत 126 मामलों को अंतिम आदेश हेतु पूर्णतः परिपक्व पाया गया है। इन मामलों की सुनवाई कर उसी दिन निस्तारण किया जाएगा तथा आदेशों की प्रमाणित प्रतियां संबंधित पक्षों को तत्काल उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त लगभग 150 ऐसे मामले, जिनमें पूर्व में विशिष्ट निदेश जारी किए गए थे, अनुपालन सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किए गए हैं। निष्पत्ति निर्देशों के अनुपालन की पुष्टि होने पर इन मामलों का भी कार्याही के दौरान अंतिम निपटारा किया जाएगा। इस श्रेणी में केवल वे ही मामले शामिल किए गए हैं जिनमें लंबित अनुपालन मामूली प्रकृति के हैं तथा जिनका तत्काल सत्यापन संभव है। न्यायालय परदर्शिता एवं सुविधा सुनिश्चित करने के लिए खुली सुनवाई प्रारूप में कार्य करेगा। निम्न बातियों के मामले अंतिम चरण में हैं, वे प्रातः 11:00 बजे न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। विधिप्रवृत्त मामलों का निस्तारण उसी दिन किया जाएगा। यह पहल उप-मंडल स्तर पर लंबित मामलों को कम करने तथा आ-न्यायिक कार्यप्रणाली की दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ नागरिकों को समयबद्ध राहत प्रदान करने के उद्देश्य से की जा रही है।

जूही जलोटा ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चंडीगढ़ में उप पासपोर्ट अधिकारी एवं कार्यालय प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला

चंडीगढ़। श्रीमती जूही जलोटा, भारतीय विदेश सेवा (2018 बैच) की अधिकारी, ने आज क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चंडीगढ़ में उप पासपोर्ट अधिकारी एवं कार्यालय प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने निवर्तमान क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी श्रीमती प्रियंका मेहतानी, भारतीय विदेश सेवा (2015 बैच) का स्थान ग्रहण किया है तथा वे क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चंडीगढ़ के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत चंडीगढ़ तथा पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों में पासपोर्ट सेवाओं की देखरेख करेंगी। श्रीमती जलोटा ने सीईडि, स्पेन तथा ब्यूनस आयर्स, अर्जेटीना स्थित भारतीय मिशनों में तथा विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली में विभिन्न पदों पर कार्य किया है।

आपदा प्रबंधन में दक्षता की ओर बढ़ते युवा: युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण का सफल समापन



पंचकूला। संयुक्त प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षी एवं नागरिक सुरक्षा, पंचकूला में 16 से 22 फरवरी तक आयोजित केंद्र प्रयोजित ह्युयु आपदा मित्र प्रशिक्षण के तहत राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के स्वयंसेवकों का सात दिवसीय गहन आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं को समुदाय स्तर पर सक्षम प्रथम प्रत्युत्तरकर्ता के रूप में तैयार करना था, ताकि वे बाढ़, आग, भूकंप जैसी प्राकृतिक अथवा मानवजनित आपदाओं में त्वरित एवं प्रभावी राहत एवं बचाव कार्य कर सकें। समापन समारोह में मुख्य अतिथि श्री चंद्रकांत कटारिया, एसडीएम, पंचकूला उपस्थित रहे। इस अवसर पर अंजु राणा, परियोजना अधिकारी (आपदा प्रबंधन), उपायुक्त कार्यालय, पंचकूला तथा डॉ. शैलजा खड्का, प्राचार्या, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेक्टर-1 पंचकूला विशिष्ट रूप से उपस्थित रही। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अनिल कुमार पांडे सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। लगभग 100 एनएसएस स्वयंसेवकों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। प्रशिक्षण पूर्ण करने पर स्वयंसेवकों को राज्य स्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए तथा उन्हें इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट (एचडी) दी जाएगी, जिनमें राहत एवं बचाव कार्य हेतु आवश्यक सुरक्षा उपकरण एवं सामग्री शामिल है।